



04 - एटम बम और गांधी: जीत किसकी होगी



05 - आर्द गूमियों पर पनपती है समृद्ध जैव विविधता



06 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रतापमानु सिंह चौहान स्मृति अखिल भारतीय...



07 - उमरते भारत के सपने को संजोता बजट

कलकत्ता

subhasaverenews@gmail.com
facebook.com/subhasaverenews
www.subhasavere.news
twitter.com/subhasaverenews

शरद की सुबह

वसंत और पतझड़ के मौसम में उजली मीठी धूप वाले दिन मैं जाऊँगा बस्तियों के पार एक विरल वन में जहाँ पलाश के फूलों की वंदनवार सजी होगी और महकती हवाएँ मेरा स्वागत करेंगी

पतियों से रिकत एक पेड़ के नीचे पीले कपड़ों में सजी एक लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी

उजास, मादकता, सुवास और निस्तब्धता से गुम्फित वह समय मेरा आनंद पर्व होगा

मैं एक दिन वहाँ जाऊँगा।

- चंद्रशेखर साकल्ले

प्रसंगवश भारत-यूरोप संवाद : दूरदर्शी रणनीति या हालात से उपजा मोड़?

सतीश झा

भा रत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: क्या यूरोप की ओर भारत का झुकाव एक लंबा रणनीतिक नजरिया है या वैश्विक दबावों और अमेरिकी अनिश्चितता की वजह से उठया गया एक कदम है?

कूटनीति में समय ही सबसे बड़ा कारक होता है। भारत का यूरोप की ओर ताजा झुकाव-जिसका ठोस रूप हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में दिखाई देता है-किसी दीर्घकालिक रणनीतिक दूरदृष्टि की पराकाष्ठा कम, और परिस्थितियों के दबाव में लिया गया एक तेज निर्णय अधिक लगता है। इतिहास बताता है कि यूरोप कभी भी भारत की रणनीतिक कल्पना के केंद्र में नहीं रहा। बदला केवल इरादा नहीं, बल्कि वह तात्कालिकता बदली जिसने वैश्विक झटकों और वांशिंगटन में लौटती अनिश्चितता के बीच भारत को तेजी से निर्णय लेने पर विवश किया।

पिछले सात दशकों तक यूरोप दिल्ली के विश्व दृष्टिकोण में परिधि पर ही रहा। भारत की विदेश नीति शीतयुद्ध के त्रिकोण से गढ़ी गई-सोवियत संघ से हथियार और ऊर्जा, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, और 1991 के बाद अमेरिका के साथ सतक निकटता। इसके उलट यूरोप भारत के लिए एक पूर्व औपनिवेशिक शक्ति और नैतिक उपदेशक बना रहा-जो मानवाधिकारों पर व्याख्यान देता रहा, लेकिन अपने बाजारों को सब्सिडी और कठोर नियमन से सुरक्षित रखता रहा।

सरकार की भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी ने गहराई का वादा किया था, पर परिणाम सीमित ही रहे। शिखर सम्मेलन औपचारिक रस्मों में बदल गए, 2013 में

व्यापार वार्ताएँ ठप पड़ गईं, और व्यापार का विस्तार तो हुआ-पर बिना किसी रणनीतिक छलांग के। 2006 में जहाँ व्यापार 47 अरब था, वह 2018 में 91 अरब तक पहुँचा, पर यह वृद्धि क्रमिक थी, परिवर्तनकारी नहीं। चीन की यात्रा इसका उलटा उदाहरण पेश करती है। वांशिंगटन के प्रारंभिक समर्थन और यूरोपीय पूंजी के प्रवाह के साथ चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी से समाहित हुआ। 2000 में लगभग 100 अरब से शुरू हुआ यूरोप-चीन व्यापार आज 700 अरब से अधिक है। पैमाना, गति और केंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया-तीनों ने इस उभार को कई गुना बढ़ाया।

भारत को ऐसी रणनीतिक अनुकूलता कभी नहीं मिली। ब्रसेल्स की नजर में वह संरक्षणवादी, सुधारों में धीमा और मॉस्को से भू-राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ देश रहा। नतीजा यह कि दशकों तक यूरोपीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से नीचे ही अटकी रही।

हालिया आँकड़े भी इसी प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। 2021 में 88 अरब से बढ़कर 2024 में भारत-ईयू वस्तु व्यापार 120 अरब तक पहुँचा। सेवाओं का व्यापार-मुख्यतः आईटी और परामर्श-तीन गुना बढ़कर 66 अरब हो गया। यह प्रगति सम्मानजनक है, पर क्रांतिकारी नहीं।

इसके विपरीत, यूई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए के साथ भारत के नए एफटीए लागू होते ही कुछ ही महीनों में निर्यात में तेज उछाल दिखा। यूरोप अंतिम बड़ा अपवाद बना रहा-केवल भारत की हिचक के कारण नहीं, बल्कि ब्रसेल्स की अपनी नियामक, राजनीतिक और रणनीतिक सावधानियों के चलते भी।

यूरोप का यह पुनर्मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। चीन की आक्रामकता, कोविड के दौरान उजागर हुई आपूर्ति

श्रृंखला की कमजोरियाँ, और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से उपजा भू-राजनीतिक टूटाव-इन सबने भारत को एक अधिक विश्वसनीय दीर्घकालिक साझेदार के रूप में उभारा। लेकिन वास्तविक गति तब आई जब अमेरिकी व्यापार नीति में अस्थिरता लौट आई।

2025 में डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही भारतीय निर्यात पर शुल्क की धमकियाँ और रूस से तेल खरीद पर दंड की बातें फिर उभरने लगीं। वर्षों से अटकी ब्रसेल्स वार्ताओं में अचानक जान आ गई। अक्टूबर 2025 के चौदहवें दौर में सफलता मिली और जनवरी 2026 में समझौते की घोषणा हुई। आधार पहले से मौजूद था; शिखर दबाव में जाकर रखा गया।

यूरोप में भारत की कूटनीति की एक गहरी संरचनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करता है। हमारी विदेश नीति अब भी व्यक्ति-प्रधान और घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक है, जबकि यूरोपीय संघ जैसे जटिल साझेदार के लिए मजबूत संस्थागत निरंतरता चाहिए।

ईयू से बातचीत द्विपक्षीय सौदेबाजी नहीं है। इसमें 27 सदस्य देशों, यूरोपीय आयोग और एक घने नियामक तंत्र से जुझना पड़ता है। 2007 में शुरू हुआ व्यापक व्यापार एवं निवेश समझौता पेटेंट, कृषि सब्सिडी और डेटा शासन जैसे मुद्दों पर वर्षों तक अटका रहा। प्रगति तब तेज हुई जब बाहरी झटकों-चीन का उदय और अमेरिका की नई अनिश्चितता-ने तात्कालिकता पैदा की।

नया समझौता कागज पर महत्वाकांक्षी है-97 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क समाप्ति, गतिशीलता प्रावधान, रक्षा सहयोग और सतत विकास प्रतिबद्धताएँ। पर महत्वाकांक्षा अपने-आप क्रियान्वयन की गारंटी नहीं देती। असली परीक्षा समन्वय की है-क्या भारत कर-प्रणाली, श्रम बाजार और अनुबंध प्रवर्तन में ऐसी घरेलू

सुधार-क्षमता दिखा पाएगा जो यूरोप की नियामक अपेक्षाओं से मेल खाए?

यदि यह साझेदारी वास्तव में परिवर्तनकारी बननी है, तो इसे प्रतीकवाद से आगे बढ़ना होगा। भारत की सेवाओं, औषधि उद्योग और विनिर्माण पैमाने को यूरोप की मशीनरी, सटीक इंजीनियरिंग और हरित तकनीक की ताकत से जोड़ने वाली पूरक आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनानी होंगी। एक क्षेत्र विशेष रूप से गंभीरता का संकेत देगा- ग्रीन हाइड्रोजन। साझा निवेश लक्ष्य, एकरूप मानक और बड़े पैमाने पर उत्पादन का विश्वसनीय मार्ग तय हुआ, तो यह साझेदारी आने वाले औद्योगिक चरण की धुरी बन सकती है। निर्णायक तत्व संस्थागत गहराई होगी। स्थायी कार्य समूह, वार्षिक व्यापार एवं नियामक समीक्षा, और सशक्त उप-राष्ट्रीय साझेदारियाँ-जैसे गुजरात-हैम्बर्ग या कर्नाटक-बेवेरिया-आकस्मिक शिखर सम्मेलनों की जगह लेनी चाहिए। इसके बिना गति राजनीतिक चक्रों की बंधक बनी रहेगी।

भारत का आर्थिक उत्थान बहु-दिशात्मक रणनीति की माँग करता है, न कि बाहरी झटकों से प्रेरित तात्कालिक पुनर्संरचना की। ईयू समझौता आवश्यक कदम है, पर इसे मजबूत नहीं, नींव माना जाना चाहिए। यदि दिल्ली इसे प्रतिक्रियात्मक विविधीकरण का अंतिम बिंदु समझेगी, तो यूरोप एक शालीन साझेदार भर रह जाएगा-पर परिवर्तनकारी नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि यह समझौता बनने में कितना समय लगेगा। सवाल यह है कि क्या भारत इसे सार्थक बनाने के लिए तैयार है। इतिहास हस्ताक्षर को नहीं, उसके बाद आने वाले ठोस परिणामों को याद रखेगा।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बजट 2026 'सुधार एक्सप्रेस' किसान-युवाओं पर जोर

● बजट 2026 में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज ● महिला, युवा, गरीब और किसान, सबका होगा कल्याण ● बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं ● ऑपरेशनसिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15 फीसदी बढ़ा ● 17 कैसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया और 'सुधार एक्सप्रेस' को जारी रखने की घोषणा की। सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और छोटी कंपनियों पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया और सुधारों का खाका पेश किया। वे 85 मिनट बोलें, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत दी।

विदेश से सामान मंगवाना होगा सस्ता, कस्टम ड्यूटी घटाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश से सामान मंगवाना अब सस्ता होगा। सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते समय की। उन्होंने आयात किए जाने वाले सभी सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 20 से घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि अब बाहर से अपने लिए सामान मंगवाना सस्ता हो जाएगा। सरकार कस्टम ड्यूटी की इस व्यवस्था को आसान बनाना चाहती है। कस्टम ड्यूटी कैसे लगती है, इसे समझना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इकनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर बताया है कि आयातित सामानों पर बैसिक कस्टम ड्यूटी लगती है जिसमें छूट दी गई है।

'विकसित भारत' के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन

निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण पर जोर देने के साथ पूंजीगत व्यय लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री ने लगभग सवा घंटा के अपने बजट भाषण में सुधारों का खाका पेश करते हुए 'विकसित भारत' के लिए बैंकों को तैयार करने को लेकर एक समिति के गठन का भी प्रस्ताव किया।



बजट की सबसे बड़ी घोषणाएँ

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

कैसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5 फीसदी शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों भी ड्यूटी फ्री। डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़, यानी 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होगा, यानी 22 फीसदी की बढ़ोतरी।

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। 15 हजार सैकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेनर क्रिप्टर लैब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे।

'गोल्डीलॉक्स' माहौल में आर्थिकी को सुनहरा टच देने की कोशिश

ललित टिप्पणी/ बजट 2026-27 अजय बोकिल

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अपने लगातार 9वें वार्षिक बजट में तात्कालिक और लोक-लुभावन लाभों की जगह चुनौतीपूर्ण माहौल में दीर्घवधि में देश का आर्थिक संरचना और स्थिरता को मजबूती देने पर ज्यादा जोर दिया है, जो आज वैश्विक आर्थिक राजनीतिक अनिश्चितता की दृष्टि से भी अहम है। तीन कर्तव्य बोधों और युवा शक्ति संचालित इस बजट वर्तमान और भावी चुनौतियों के मद्देनजर कई योजनाएँ और घोषणाएँ हैं। इसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। राजजुट इसके अन्तर्गत देश के शीयर बाजारों को यह बजट रास नहीं आया तो इसका मुख्य कारण निवेशकों की सावधानी, सरकार की वित्तीय नीतियों तथा वैश्विक आर्थिक-राजनीतिक अनिश्चितताओं का कारण ज्यादा है। जिसमें टैरिफ-रिफॉर्म और घटता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है। इसके बाद भी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात फीसदी से ज्यादा बनी हुई है तो इसकी वजह आर्थिक दृष्टि से भारत में 'गोल्डीलॉक्स' (सही आर्थिक रफ्तार और समुचित रोजगार सृजन) स्थिति के चलते बाजार को और बेहतर, कल्पनाशील, साहसिक तथा ज्यादा रोजगारोन्मुखी बजट की अपेक्षा थी। अच्छी बात यही है कि वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को काबू में रखा है। आर्थिक वृद्धि विकास दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है। सरकार ने अब सेमी कंडक्ट और एआई जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने पर ध्यान दिया है, जिसमें भारत वैश्विक दौड़ में पिछड़ता नजर आ रहा था। वित्त मंत्री ने पर्यटन को आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन माना है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट को गौर से समझें तो वित्त मंत्री ने जिन राज्यों को सौगातों से खुश किया है, वो वही राज्य हैं, जिनमें इस साल अथवा आगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जहाँ चुनाव नहीं हैं, उन राज्यों को कोई प्रत्यक्ष और भौतिक लाभ का जिज्ञा बजट में नहीं है। एक ओर राजनीतिक नुकसान भरपाई बापू के नाम पर 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना' की घोषणा के रूप में की गई है। यह खादी को बढ़ावा देने की योजना है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में से गांधी का नाम हटकर उसे जयराज योजना में तब्दील कर दिया था। जिसका विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए इसे बापू का अपमान करार दिया था। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस आरोप का खंडन किया, लेकिन इसकी नुकसान भरपाई के रूप में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लाई गई है। हालांकि खादी और ग्राम स्वराज के बीच क्या तार्किक सम्बन्ध है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

वित्तमंत्री ने इस बात का गर्व के साथ उल्लेख किया कि यह पहला वार्षिक बजट है, जो कर्तव्य ध्वन में तैयार हुआ है। लिहाजा यह बजट भी तीन कर्तव्य बोधों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य यानी सतत और स्थायी आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना, दूसरा है गरीब, कमजोर और वंचितों का ख्याल रखना और तीसरा कर्तव्य है भविष्य के लिए आर्थिक विकास की बुनियाद को मजबूत करना। वित्त मंत्री का मानना है कि आर्थिक व्यवस्था में ढांचगत सुधार करने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन में वृद्धि अर्थ व्यवस्था को बल और गति मिलेगी, जिससे भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक मजबूती के साथ खड़ा रह सकेगा। हालांकि आर्थिक जानकारों का कहना है कि देश में रोजगार बढ़ तो रहा है, लेकिन अस्थायी गिग वर्कर्स के रूप में, जिनको नौकरी और रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। युवाओं को स्थायी और निरंतर रोजगार चाहिए, जो उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन सके। भारत में बड़ी समस्या श्रम आधारित उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की है। यह चुनौती एआई आने से और बढ़ गई है, जिससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों में भारत अन्य देशों की तुलना में अभी पीछे है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में कुल खर्च अनुमान 53.5 लाख करोड़ रु. ज्यादा है, जो वर्ष 2025 26 को तुलना में करीब 4 लाख करोड़ रु. ज्यादा है। सकारात्मक बात यह है कि सरकार अधीसरचना विकास पर लगातार बल दे रही है।

- शेष पेज 2 पर

कोशिश यही है कि हर घर में लक्ष्मी जी पधारें

● बजट पर बोले पीएम मोदी बताया ऐतिहासिक
● बजट में नारी शक्ति और युवा सोच का प्रतिबिंब

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट 2026 की घोषणा के बाद देश को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने कहा, ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये युवा शक्ति का बजट है। इसमें युवा सोच है, युवा के सपने हैं। इस बजट से युवाओं के लिए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा, इस बजट से आत्मनिर्भर भारत को उड़ान मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डिजिटल फ्रंट कॉरिडोर, देशभर में वाटर वेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बांड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।



पीएम मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री का विकसित भारत @2047 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपये खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला



छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डेली कॉलेज इंदौर में केन्द्रीय बजट पर विषय-विशेषज्ञों से

संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के बाद केन्द्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट की सभी क्षेत्रों में सहानुभूति हो रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टैक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाडू अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री का अभिवादन किया।



कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज काफी सस्ता होगा

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएँ हैं। अभी



5 नव कस्टम ड्यूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्क्युलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों की ड्यूटी फ्री कर दी गई है। रक्षा बजट 15 फीसदी बढ़ा, फॉसिस के आधुनिकीकरण पर 22 फीसदी ज्यादा खर्च होगा- ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में

सीतारमण ने जियो-पॉलिटेक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22 फीसदी की बढ़ोतरी है। विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी 3 आयुर्वेदिक एप्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएगी।

रेल और जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ऐलान

7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बंगलुरु, चेन्नई-बंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। बेटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी सरकार ने लिथियम-आयन बेटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बेटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। वहीं, सोलर प्लांट बनाने में इस्तेमाल होने वाले 'सोडियम एंटीमोनेट' पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा।

बजट के बाद हाहाकार, औंधे मुंह गिर गया शेयर बाजार

बीएसई सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। बजट के बाद आज यानी 1 फरवरी (रविवार) को शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1546



अंक यानी करीब 2 फीसदी गिरकर 80,722 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 अंक टूटा, ये 24,825 के स्तर पर बंद हुआ। सरकार ने प्यूचर्स पर लगने वाले

सिक्वोरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) को 0.02 से बढ़ाकर 0.05 फीसदी किया। ऑफ़िश प्रीमियम और एक्सरसाइज पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15 फीसदी किया। इस वजह से बाजार में यह गिरावट आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद सेंसेक्स 1,800 अंक और 550 अंक तक गिर गया था। वहीं सुबह 9.15 बजे सेंसेक्स 100 अंक की गिरावट के साथ 82,156 के स्तर पर खुला था। निफ्टी भी करीब 50 अंक की गिरावट के साथ 25,275 के स्तर पर ओपन हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और सिर्फ 3 में तेजी रही। अडाना पोर्ट्स के शेयर में 6 फीसदी तक की गिरावट रही।

पर्यटन-20 दृष्टि प्लेन पर 10 हजार गाइड्स ट्रेड किए जाएंगे

20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों। 2026-27 में विदेश पैसा भेजने पर लगने वाले टैक्स कलेक्ट्रेड एड सोर्स को कम करने का ऐलान किया है। अब विदेश में पढ़ाई सस्ती होगी।

मोदी सरकार के बजट 2026 में महिलाओं को मिली खास सौगात

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का बजट पेश किया। हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री के पितासे में महिलाओं के लिए कुछ खास सौगात देखने को मिली। केंद्र



सरकार ने लखपति दीदी योजना को जारी रखने की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज रहित लोन दिया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। इस लोन पर महिलाओं को सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद वित्त मंत्री ने 'शी मार्ट्स' की घोषणा की है। ये मार्ट्स स्वयं सहायता उद्यमियों की ओर से संचालित किया जाएगा और रीटेल आउटलेट के रूप में ऑपरेट करेगा। केंद्र सरकार की इस नई स्कीम का उद्देश्य महिला उद्यमियों की

पहुंच बढ़ी बाजार तक सुनिश्चित करना है। इसके तहत महिलाएं न सिर्फ अपना खुद का ब्रांड बना सकेंगी, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगी। इससे स्थानीय स्वयं सहायता समूह भी मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्राओं को भी बजट में शानदार सौगात दी है। उन्होंने हर जिले में ग्लॉस हॉस्टल खोलने की घोषणा की है। देश के लगभग 700 से ज्यादा जिलों में छात्राओं के रहने के लिए ग्लॉस हॉस्टल की नींव रखी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने महिलाओं और युवतियों के लिए कई सारी सुविधाओं का ऐलान किया है।

बजट की बड़ी घोषणाएं

- इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क

हटाया। अभी 5 फीसदी शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्क्युलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों की ड्यूटी फ्री।

- डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़, यानी 15.2 फीसदी की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के

मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22 फीसदी की बढ़ोतरी।

- 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी। 3 आयुर्वेदिक एप्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल

हब भी बनेंगे। 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लेब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। जहां विशेष व्यवस्था रहेगी।

'युवाओं के पास नौकरी नहीं, संकट में किसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने युवाओं, किसानों, निवेशकों का जिक्र करते हुए दावा किया कि ये बजट भारत के असली संकटों से अनजान है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में भारत के

सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है।

मणिपुर में उग्रवादी रंगदारी मांग रहे, डर से बाजार बंद

व्यापार संगठन ने 5 किमी लंबी रैली निकाली, सैकड़ों लोगों ने राज्य छोड़ा

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में उग्रवादी संगठन हर सेक्टर के कारोबारियों को फोन कर रंगदारी मांग रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास हमारा लेखा-जोखा है। उनके डर बाजार बंद होने लगे हैं। इसके विरोध में शनिवार को इंफाल में हजारों लोगों ने 5 किमी लंबी रैली निकाली। यह रैली सेव मणिपुर अभियान के तहत कोकोमी नामक संगठन ने आयोजित की थी। कर्ज में डूबे मारवाड़ी, पंजाबी कारोबारी भी राज्य छोड़ रहे हैं। इस बाजार से जुड़े मारवाड़ी समुदाय के 500 परिवार में से 40-50 परिवार, पंजाबी समुदाय के

100 परिवार में से 20-25 परिवार बिजनेस ठप होने से पलायन कर चुके हैं। राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थांगल और पाउना बाजार में 60-65 फीसदी ही व्यापार हो रहा है। मणिपुर एफएमसीजी एसोसिएशन के प्रेसीडेंट विजय पाटनी कहते हैं, चुराचांदपुर, कांपोक्पी और चंदेल जिलों तथा आसपास के इलाकों में 30-37 फीसदी कारोबार होता था, जो अब बंद है। उन्होंने बताया कि थांगल-पाउना बाजार में मारवाड़ी, जैन, पंजाबी, बिहारी, बंगाली सहित कई समुदाय के लोग बिजनेस करते थे। मणिपुर में कोई फेक्ट्री या मैनुफैक्चरिंग यूनिट नहीं है।



काशी में रविदास जयंती पर 3 किमी लाइन, भारी भीड़

10 चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे भक्त, डॉलर की माला पहनाई

वाराणसी (एजेंसी)। रविवार को संत रविदास की जयंती रही। इस मौके पर काशी में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पूरी तरह से रैदासियों का शहर बन गया है। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही मंदिर के बाहर करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग घंटों इंतजार करके संत रविदास के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ में एक सांड भी घुस आया। सेवादारां ने कड़ी मशक्कत कर उसे बाहर निकाला। इससे पहले करीब 1000 से ज्यादा एनआरआई 10 चार्टर्ड विमानों से आए। उन्होंने संत रविदास को डॉलर की माला पहनाई। दोपहर में नगीना सांसद चंद्रशेखर भी पहुंचे। संत रविदास के दर्शन किए। कह- गरीबी, लाचारी सब खत्म हो जाएगी। यह समाज आशावादी है। मंदिर के पास 150 फीट ऊंची रविदासी पताका भी फहराई गई है। मंदिर को करीब 200 किलो से ज्यादा सोने से सजाया गया है।



टी-20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होगा

पाकिस्तान सरकार का ऐलान; बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी के महामुकाबले का बॉयकॉट किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप में के खिलाफ मैच का बॉयकॉट किया जाएगा। पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। दोनों टीमों 15 फरवरी को कोलंबो में एक-दूसरे से भिड़ने वाली थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंट्री दी थी। इसके विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उनकी टीम भारत से वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी। टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन भारत से मैच नहीं- पाकिस्तान सरकार



पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत

सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड टी20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है।..

पेज-1 का शेष त्वरित टिप्पणी

इन्में सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दवा उद्योग भारत की निर्यात व्यवस्था का बड़ा घटक है। वित्त मंत्री ने बजट में 'औद्योगिक संप्रभुता' का दांव चलाते हुए 'बायो फार्मा शक्ति' के लिए 10,000 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव रखा है। ताकि भारत औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस की संज्ञा दी गई है। इसके तहत 6 प्रमुख कर्तव्यों और 7 फोकस सेक्टरों की पहचान की गई है, जिनका उद्देश्य भारत को 'इंडस्ट्रियल सॉल्यूटिव' यानी औद्योगिक संप्रभुता को सुनिश्चित करना है। बायो फार्मा शक्ति के अंतर्गत ज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के जरिए विकास करना और किफायती दवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इसके तहत देश में बायो-फार्मा के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। बजट में 40 हजार करोड़ का प्रावधान कर 'सेमीकंडक्टर मिशन' को विस्तार दिया गया है। ताकि इस क्षेत्र के लिए स्किलड वर्क फोर्स तैयार किया जा सके। दुनिया में दुर्लभ खनिजों के लिए चल रही मारामारी के बीच बजट में 'रेयर अर्थ मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए चार राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का चयन किया गया है। ताकि दुर्लभ खनिजों का आयात कम कर हम घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भर हो सकें। बजट में छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई को 'चैम्पियन' बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सरकार की नीतियों के चलते एमएसएमई मुश्किल में हैं। बजट में अधोसंरचना विकास की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण घोषणा अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू करने की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसकी शुरुआत ओडिशा में

'गोल्डीलॉक्स' माहौल में आर्थिकी को सुनहरा टच देने की कोशिश

नेशनल वॉटरवे 5 से होंगी, जो तालचर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेंगी।

केंद्रीय बजट में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, कैंसर के इलाज के लिए जरूरी 17 दवाएँ सस्ती करने का ऐलान है। इसके लिए देश में पांच बड़े मेडिकल हब बनाए जाएंगे। साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 लाख सहायक स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1.5 लाख केयर गिवर्स भी तैयार किए जाएंगे। एप्स की तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में एक नया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। शिक्षा के लिए बजट पिछले वर्ष की तुलना में 8.27% बढ़ा है। बजट में स्वास्थ्य, कौशल विकास, डिजाइन, एनीमेशन, आयुष, पशुपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नई संस्थाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही भविष्य की तकनीकों, एमएसएमई और ग्रीन एनर्जी के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। रोजगार के महदेजर AVGC यानी तहत एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में पेशेवरों की बढ़ती मांग को देखते हुए 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि इससे 20 लाख नौकरियां सृजित होंगी। बजट में बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के

पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने की योजना है। साथ ही, हर जिले के STEM संस्थानों में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके अलावा, चार टेलीस्कोप सुविधाओं को नया रूप दिया जाएगा या सुधार किया जाएगा, ताकि छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

वित्त मंत्री ने बजट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मार्स्टेन ट्रेल्स बनाने का ऐलान किया। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनाएंगे। इससे एडवेंचर टूरिज्म करने वाले पर्यटकों का रोमांच दोगुना हो जाएगा। ओडिशा केरल में टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। बजट में एक और अहम घोषणा 'आईआईएम प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड्स' की है। देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कदम पर्यटन को अनौपचारिक से पेशेवर क्षेत्र में बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे विदेशी पर्यटकों को विश्वस्तरीय सेवा मिलेगी और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बजट में देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे सारनाथ, हरिनापुर को 'वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर-पूर्व में बौद्ध सर्किट और हिमाचल-कश्मीर में नई हार्किंग ट्रेल्स बनेंगी। देश के सभी ऐतिहासिक स्थलों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 5 वर्षों में सिटी इकॉनॉमिक रीजन (CERs) को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के विशेष फंड का प्रस्ताव

रखा है। ताकि ये क्षेत्र स्थानीय और राष्ट्रीय विकास के केंद्र बन सकें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्सपेयमेंट के लिए क्लरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। बजट में संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च करने का ऐलान किया। इसके साथ उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत एजुकेशन और मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के मामले में लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है।

इस बजट के बाद भारतीयों के लिए विदेश यात्रा सस्ती होगी। यात्रा पैकेज की बिक्री पर लगने वाले टीसीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की ओर से दिए गए मुआवजा को कर से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 एक अप्रैल से लागू होगा और इसके नियम और कर रिटर्न फॉर्म जल्दी ही अधिसूचित किए जाएंगे। संक्षेप में कहें तो यह बजट दीर्घकालिक आर्थिक आकांक्षाओंको संबोधित करने वाला है, भले ही इससे तत्काल कोई बड़ा लाभ नजर नहीं आ रहा हो। पीएम मोदी ने इसे 'महत्वाकांक्षी' बजट कहा है। आज भारत की आर्थिकी के समान सबसे बड़ी चुनौती अपनी आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने और बड़ी आबादी को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ रोजगार देने की है। बजट इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ता दिखाई देता है।

उमरिया के खेत में पहुंचा टाइगर, दशत में ग्रामीण

दमना गांव के मानपुर-ताला परिक्षेत्र की टीम निगरानी में जुटी



उमरिया (नप्र)। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर परिक्षेत्र में दमना गांव के पास खेतों में एक बाघ देखा गया है। रविवार को खेत में बाघ के बैसे होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी मिलने के तुरंत बाद, टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारी और गाइडों को तैनात किया गया है। मानपुर बफर और ताला परिक्षेत्र की एक संयुक्त टीम लगातार बाघ की निगरानी कर रही है। सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने ग्रामीणों को घटनास्थल से दूर कर दिया है। बताया गया है कि बाघ खेतों की झाड़ियों में बैठा हुआ है और उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्थिति नियंत्रण में- मानपुर बफर परिक्षेत्र के अधिकारी मुकेश अहिरवार ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ क्षेत्र में लगातार गश्त भी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके।

बजट 2026 पर नेताओं, मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं

केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को नई गति देता है। बजट में समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण और पंच प्राण के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को इस ऐतिहासिक बजट के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बजट का उद्देश्य समग्र और सर्वस्पर्शी विकास को सुनिश्चित करना है, ताकि देश के हर क्षेत्र और नागरिक तक विकास की लहर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल संपर्क को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल संपर्क को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगी।

समावेशी विकास के संकल्प के साथ 'विकसित भारत 2047' को सशक्त करने वाला बजट : मंत्री श्री सारंग

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को मजबूती देने वाला, परिपूर्ण और नए आयाम स्थापित करने वाला है। यह बजट आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के संकल्प के साथ देश के हर वर्ग के कल्याण, संरक्षण और सर्वांगीण विकास को स्पष्ट दिशा देता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि केंद्रीय बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और विश्वास का सशक्त प्रतिबिम्ब है। यह बजट सुधारों की निरंतर यात्रा को और अधिक मजबूत करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक स्पष्ट और ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है।

महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर देश का नाम करें रोशन: मंत्री श्री कुशवाह

135 जरूरतमंद महिलाओं को उपलब्ध कराई 'आटा चक्की'

भोपाल (नप्र)। सेवा पखवाड़ा एवं विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं उद्यमिता मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह द्वारा अनुवा एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 135 जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'आटा-चक्की' मशीनें उपलब्ध कराई गईं। ये सभी ऐसी महिलाएँ हैं जो अभावों में अपने परिवार के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। मंत्री श्री कुशवाह ने सीएसआर फंड से 'आटा-चक्की' मशीनें उपलब्ध कराई हैं। रविवार को पुराने रेलवे स्टेशन जीवाजीगंज परिसर ग्वालियर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।

सामाजिक न्याय एवं उद्यमिता मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नए भारत व समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लिया है। इसी भावना के साथ आज ग्वालियर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने 'आटा चक्की' मशीनें लेने आई महिलाओं का आह्वान किया कि आप सब आत्मनिर्भर बनकर देश को मजबूत करें, जिससे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप अपना देश विश्वभर का नेतृत्व करें। मंत्री श्री कुशवाह ने महिलाओं से यह भी कहा कि यदि परिवार में कोई नशा करता हो तो उसे नशे से दूर करने की पहल भी करें।

श्री जयप्रकाश राजौरिया ने कहा कि मंत्री श्री कुशवाह ने आटा चक्की उपलब्ध कराकर जरूरतमंद महिलाओं को नई ताकत देने का काम किया है। निश्चित ही इससे महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगीं।

उन्होंने कहा कि उद्यमिता मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह द्वारा सीएसआर मद से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। श्री अभय चौधरी ने भी जनकल्याण व जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह निरंतर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री रमेश अग्रवाल, नगर निगम के पूर्व सभापति श्री राकेश माहौर सहित जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में महिलाएँ उपस्थित थीं।

शौच के लिए गई मंदबुद्धि नाबालिग को उठा ले गया दरिदा, सूने मकान में 24 घंटे बंधक बनाकर किया रेप



मैहर (नप्र)। जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में इसानियत को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। यहां हवस के भूखे एक दरिदे ने 15 साल की मंदबुद्धि (दिव्यांग) किशोरी को अपना शिकार बनाया है। आरोपी ने शौच के लिए गई किशोरी को अगवा कर 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ठीक से बोल भी नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों ने अपनी लापबेती मां को बता दी। पुलिस ने तत्परा दिखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

अभी नाबालिग हे पीड़िता

जानकारी मुताबिक, पीड़िता की उम्र 15 साल 9 महीने है और वह मानसिक रूप से कमजोर है। बीते 28 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे वह घर से रामसागर खेत की तरफ शौच के लिए गई थी। जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी, तो घरवाएँ परिनजों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।

24 घंटे बाद आरोपी के साथ दिखी

लापता होने के करीब 24 घंटे बाद परिनजों ने देखा कि पीड़िता पड़ोस में रहने वाले दीपू कोल के साथ घर की ओर आ रही है। जैसे ही दीपू की नजर पीड़िता की मां पर पड़ी, वह डर के मारे किशोरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ।

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम: उपमुख्यमंत्री देवड़ा



उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने मध्यप्रदेश के नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण को कोटि-कोटि बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यप्रदेश जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेज गति से अपनी जोड़ीपी में बढ़तेर कर रहा है। पूंजीगत

व्यय में हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अब कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है। केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष पूंजीगत सहायता योजना में 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जो वित्त वर्ष से 50 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इस योजना में मध्यप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना होगी। इससे अधोसंरचनात्मक गतिविधियों को विस्तार देने में भी मदद मिलेगी। अन्य राज्यों की तुलना में म.प्र. में एमएसएमई विकास का सबसे अच्छा इको-सिस्टम बना है।

इस बार का बजट पीएम मोदी के भाषण का बिल्कुल उल्टा: जीतू पटवारी

जीतू पटवारी ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का वादा किया था। कृषि को लेकर उनके जो भाषण थे, इस बार उनके विपरीत बजट आया है।



संतुलित और जनकल्याणकारी बजट: मंत्री श्रीमती उड्के

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्ति उड्के ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट जल सुखा, स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाला है।

विकास और जनकल्याण को समर्पित बजट: सिलावट

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट विकास और जनकल्याण को समर्पित है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का यह बजट देश के समग्र विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण, कृषि एवं जल संसाधन प्रबंधन और आधारभूत संरचना के विस्तार की दिशा में सकारात्मक पहल है। बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को लाभ पहुंचाने का स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाई देता है, जिससे मध्यप्रदेश को व्यापक लाभ मिलेगा।

नीमच-मंदसौर में ओलावृष्टि, सड़के ओलों से ढंकी

ग्वालियर-उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश, फसलें खराब, 14 जिलों में अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। कई जिलों में बारिश, आंधी, घना कोहरा और ओलावृष्टि देखने को मिली। मंदसौर जिले के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ के ग्राम झरड़ा से ओलावृष्टि के दृश्य बढ गई है।

रविवार शाम करीब आधे घंटे तक तेज बारिश और ओले गिरे, जिससे सड़क किनारे बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई। कई जगह लोग घर के आंगन में फावड़े से ओले समेटते नजर आए। नीमच जिले के पालसोडा और भंवरसा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई, जहां नजारा मिनी कश्मीर जैसा दिखा। ओलों और बारिश से किसानों की चिंता बढ गई है।

दतिया-खजुराहो में छाया रहा घना कोहरा- प्रदेश के दतिया और खजुराहो में घना कोहरा छाया रहा। यहां दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्वालियर, उज्जैन, धार और मुरैना में रात से सुबह तक बारिश होती रही, जबकि भोपाल में सुबह 9 बजे तक कोहरे का असर रहा। मौसम में बदलाव के बावजूद बड़े शहरों में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। केवल खजुराहो, राजगढ़ और नौगांव में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में गेहूं की फसल आड़ी हो गई, जिससे नुकसान की आशंका है।



नीमच

मंदसौर

14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट- मौसम विभाग के अनुसार दतिया, खजुराहो, ग्वालियर, नौगांव, सतना, रीवा, उज्जैन, श्योपुर, राजगढ़, रतलाम, गुना, दमोह, मंडला, टीकमगढ़ और मलाजखंड में कोहरे का असर ज्यादा रहा। वहीं नीमच, मंदसौर सहित 14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और बादल बने रहने की संभावना है। इधर, कड़के की टंड और कोहरे के बीच प्रदेशभर में माघ पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाई गई। नमदा तटों पर लोगों ने स्नान कर दान-पुण्य किया।

अगले तीन दिन का पूर्वानुमान

2 फरवरी- ग्वालियर, भोपाल, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना।

3 फरवरी- ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में कहीं-कहीं बारिश।

4 फरवरी- छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में बारिश का अलर्ट, जबकि ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया समेत कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा।

कार ने बच्ची को टक्कर मारी, मौत

पिता का हाथ छुड़ाकर सड़क पार करने

का प्रयास करते समय हुआ हादसा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के टैटेडखड़ी इलाके में तेज रफ्तार कार ने 6 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी चालक अपनी ही कार से बच्ची को इलाज



आसिया अली, मृतक

के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार देर रात की घटना है। 6 वर्षीय आसिया अली, पुत्री इकबाल अली, परेवा खेड़ा (पतलोन) की रहने वाली थी। बच्ची बीते तीन दिनों से वायरल फीवर से पीड़ित थी। इसी कारण उसके पिता उसे गांव के नजदीक हाईवे पर स्थित एक क्लीनिक में दिखाने पहुंचे थे। डॉक्टर ने जांच के बाद कुछ जल्द ही दवाइयां दीं। इसके बाद पिता पैदल बच्ची को घर लेकर जा रहे थे।

फूफा की अवैध पिस्टल से लगी थी बच्चे को गोली

कुख्यात सीरियल किलर का साथी रहा है फूफा

वाहिद; इब्राहिम का शव देखकर मां बेसुध

भोपाल (नप्र) मां और भाभी ग्राउंड फ्लोर पर खाना खा रही थीं। इसी बीच पटाखे जैसी आवाज आई। भाभी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचीं, वहां इब्राहिम खून से लथपथ पड़ा था। देखते ही भाभी बेहोश हो गईं। मं कमरे में अंदर पहुंचा, जहां भतीजे को खून से सना देख मेरे होश उड़ गए। इतना कहते ही भोपाल में गोली लगने से जान गंवाने वाले तीसरी कक्षा के छात्र इब्राहिम के चाचा रेहान का गला रूधने लगा। सिसकते हुए रेहान ने बताया कि घटना के समय उनके बड़े भाई रिजवान घर में मौजूद नहीं थे।

वे दोस्तों के साथ पार्टी करने पर लथपथ सड़क स्थित एक छाने पर गए हुए थे। बच्चे को जमीन पर अचेत देख आनन-फानन में मैं पड़ोसियों की मदद से उसे गोद में लेकर कमला नेहरू अस्पताल रवाना हुआ। इसी बीच बेहोश भाभी को होश आ गया और वह भी मेरे साथ अस्पताल जाने की जिद करने लगीं। मैं उन्हें भी साथ ले गया जल्द ही 1 घंटे बाद बड़े भाई भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में इलाज के दौरान भतीजे की शनिवार की सुबह



इब्राहिम, मृतक

मौत हो गई। इब्राहिम बहुत चंचल स्वभाव का था और बहुत प्यारा था। उसकी मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। इब्राहिम को शनिवार की रात बाद नमाज ए ईशा छोला थाना क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बेटे की मौत के बाद से सदमे में आए माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस की अब तक की जांच में यह साफ नहीं हो सका है कि बच्चे ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है या खेल-खेल में गोली चली है।

एसीपी बोले-सुसाइड के एंगल पर शुरू की जांच- एसीपी राकेश सिंह बघेल ने बताया कि बच्चे के कनपटी पर गन शॉट के निशान आए हैं। पीएम करने वाले

डॉक्टरों ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चे ने सुसाइड किया है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इस बात का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। परिनजों ने भी घर में बच्चे को किसी भी प्रकार की डांट-फटकार किए जाने की बात से इनकार किया है। बच्चे के पिता रिजवान के बयानों में यह साफ हुआ है कि शुक्रवार को उनके घर में सफाई कार्य किया गया। इस दौरान बच्चे के हाथ में घर में रखी अवैध पिस्तौल जो रिजवान के जेजा वाहिद नूर की बताई जा रही है। इसे उसने परिनजों की जानकारी के बगैर अपने पास छुपाया। देर रात इसी पिस्तौल से गोली चली और बच्चे की मौत हो गई।

देश के सर्वांगीण विकास का बजट: ऊर्जा मंत्री श्री तोमर



केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट को ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने देश के सर्वांगीण विकास का बजट कहा है। उन्होंने जनता को समर्पित, विकासोन्मुख और समावेशी बजट बताया है। मंत्री श्री तोमर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग, सभी को राहत देने वाला है।

जनता के हित का बजट, छात्राओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार व विकास का बजट: खाद्य मंत्री श्री राजपूत

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जनता को समर्पित, विकासोन्मुख और समावेशी बजट बताया है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि बजट में मध्यप्रदेश को मिली सौगातें राज्य के शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेंगीं। हर जिले में गलर्स हॉस्टल निर्माण की घोषणा से विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण अंचलों की छात्राओं को सुरक्षित आवास मिलेगा, जिससे वे बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगीं। यह निर्णय बेटियों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

केंद्रीय बजट में महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए समावेशी दृष्टिकोण: सुश्री निर्मला भूरिया

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देना सरकार की संवेदनशील एवं दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बाल संरक्षण से जुड़ी पहलों को मजबूती मिलने से जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत होगी।

संपादकीय

सुनेत्रा पवार: भाजपा का खेला !

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित) के दिवंगत नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार के दो दिन बाद ही उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार का राकपा विधायक दल का नेता चुना जाना और तत्काल उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेना न केवल हैरान करता है बल्कि साफ संकेत देता है कि अब आगे राकपा भाजपा के हिस्सा से चलेंगी। इसके पीछे एक सुनियोजित सियासी रिक्रूट है। अजित पवार ने राज्य में भाजपा के साथ सत्ता में साझेदारी करते हुए भी पार्टी की अलग पहचान बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन राकपा में वही होगा, जो भाजपा चाहेगी। शिवसेना (उद्धव) के सांसद संजय राउत ने इस जल्दबाजी पर सवाल उठाया है कि आखिर शपथ लेने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि शोकावधि समाप्त होने का इंतजार भी नहीं किया गया। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाकर भी वित्त जैसा अहम विभाग नहीं दिया। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने की बधाई दी, उसी से रणनीति साफ हो गई। सवाल यह है कि राज्य में शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के साथ अच्छा खासा बहुमत होने के बाद भी बीजेपी ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम क्यों बनाया? गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महायुक्ति के झंडे तले लड़ा था, एनसीपी और शिवसेना (शिंदे) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी 132 सीटें जीत कर अकेले बहुमत हासिल करने के करीब पहुंच गई थी। फिर भी उसने 57 सीट वाली शिवसेना और 41 सीट वाली एनसीपी को सरकार का हिस्सा बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राज्य की राजनीति में कई बिंदुओं को साधा है। पहला तो यह कि भाजपा और शिवसेना की विचारधारा भाजपा के समान है, लिहाजा उससे भाजपा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन राकपा महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी ताकत है। उसमें संघमारी करना भाजपा का लक्ष्य रहा है। हकीकत में मराठा लॉबी पर शरद पवार का असर खत्म करने के लिए भाजपा ने यह दांव चला है। यही कारण है कि राकपा विधायक दल में निर्णय ले लिया गया और सुनेत्रा के ससुर शरद पवार को इसकी जानकरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं सुनेत्रा पवार द्वारा राज्यसभा की सीट खाली करने पर उनकी जाहद पार्थ पवार को भेजना का फैसला भी कर लिया गया। शपथ लेने से पहले सुनेत्रा शरद पवार से मिलने तक नहीं गईं। इस घटनाक्रम के बाद राकपा के एक होने की संभावनाओं पर भी पलौता लग गया है। उधर शरद पवार ने फिर से राज्यसभा जाने से इंकार कर दिया है। वैसे भी उनके पास विधानसभा में इतनी सीटें नहीं हैं कि वो राज्यसभा में जा सके। अब संभावना इस बात की है कि राकपा शरद पवार वाला धड़ अंततः बीजेपी में ही शामिल हो जाए। या फिर सुनेत्रा पवार को नेतृत्व स्वीकार कर राकपा के दोनों धड़ों का विलय हो जाए। लेकिन उस स्थिति में शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले का क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर भाजपा का सुनेत्रा दांव महाराष्ट्र की राजनीति से शरद पवार की ताकत को पूरी तरह खत्म करना है और प्रकाशर से सात दशकों से हवाही रही मराठा लॉबी को भी कमजोर करना है। जिसमें वह फिर्तलाह तो सफल होती दिखती है।

एटम बम और गांधी: जीत किसकी होगी



नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

पिछले 3-4 दिनों में अमेरिका जिस प्रकार के कदम बड़ा रहा है, वह सारे विश्व के लिए चिंताजनक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद न केवल दुनिया बल्कि स्वतः अमेरिका का समाज तथा विदेशी बीजाधारक भी निरंतर आशंकित रहते हैं कि ट्रंप क्या कब कदम उठा सकते हैं यह कोई नहीं जानता? अमेरिका कुछ दशकों के पूर्व तक दुनिया में लोकतंत्र का अग्रणी देश माना जाता था। यद्यपि वहीं संपन्नता तो आई ही परंतु समता नहीं थी। संपन्नता भी दुनिया के हितधारक बेचकर, आर्थिक शक्ति को दम पर दूसरे देशों को लूटकर या अन्य प्रकार से शोषण कर यह संपन्नता अर्जित की गई थी। अमेरिकी लोकतंत्र पूंजीशाही का और कारपोरेट का लोकतंत्र रहा परंतु इस जीवनशैली में उदारवाद के कुछ गुण भी थे। अब वह पूंजीवादी लोकतंत्र के साथ साथ कट्टरपंथी और व्यक्ति नियंत्रित तानाशाह लोकतंत्र में बदल रहा है। अमेरिका की प्रणाली संसदीय नहीं बरन राष्ट्रपति प्रणाली है। अमेरिका का संवैधानिक ढांचा राज्यों को अधिकार तो देता है परंतु समूचे देश के नियंत्रण व निर्णय के अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। अब स्थिति यह है कि श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कई सदियों के लोकतांत्रिक इतिहास को भुलाकर अपने देश के हर क्षेत्र को चाहे वह पूंजी का हो, व्यापार का हो, शिक्षा का हो, विदेश नीति का हो, अपने सीधे नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। मैं मानता और जानता हूँ कि कई मजहबों जमातों में कट्टरपंथ का गहरा प्रवेश है कुछ इसलिए भी की उनके धर्मग्रंथ उन्हें अपने ही विचार के लिए अंतिम रूप से श्रेष्ठ मानने के लिए प्रेरित करते हैं और इसका परिणाम अर्थों के प्रति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शूणा और दुर्भाव में होता है। इसके भी किर्तने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। हालांकि इन मजहबों प्रतिक्रियाओं का नुकसान अभी तक उन्हीं मुल्कों को ज्यादा उठाना पड़ा है जिनकी तरफसे प्रतिक्रियां हुई थीं। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद समूची दुनिया ने अमेरिका का समर्थन किया और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के साथ-साथ वर्षों तक अफगानिस्तान में अपने सेना का नियंत्रण बना के रखा। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान को पैदा करने का काम भी अमेरिका ने ही किया था यद्यपि तालिबान के शासन के पहले भी वह इस्लामिक देश ही था, उसका इस्लामिक शासक था परंतु रूस समर्थक था और तालिबान ने महत्व के नाम पर अमेरन शासक की हत्या कर, उस चौराहे पर टांग दिया था। बाद में जब तालिबान ने महसूस किया कि वे ही शक्तिमान है तो उसने अमेरिका पर आतंकवादी हमला किया और परिणामस्वरूप अफगानी अनेकों वर्षों तक गुलामी में रहे और पिटे और मिते।

ईरान में शाह की सत्ता को टटाने के बाद, खामर्नधर्मगुरु की सत्ता आई और जब उसने शाह की संपत्ति को अमेरिका से वापस मांगा और

अमेरिका के द्वारा वापिस नहीं दिए जाने पर, ईरान में अमेरिका की लगाई गई पूंजी को जन्त किया वहीं अमेरिकी सत्ता के खिलाफ शक्तियों के साथ देस्ताना सम्बंध शुरू किया।

ईरान को काबू करने के लिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को आगे बढ़ाया और ईरान बनाम इराक की आग लगाई। प्रारंभिक दौर में सद्दाम हुसैन अमेरिका की आँख के तारे रहे। यहाँ तक की उस दौर में चालीस लाख से अधिक लोग मारे गए परंतु जब सद्दाम ने अपने मर्जी से राज करना शुरू किया और अमेरिकी डॉलर को चुनौती देकर यूरो को बढ़ावा दिया, तेल के व्यापार को यूरो में बढ़ाने का प्रयास किया तो नरसंहारक हितधारों के नाम पर अमेरिका ने सद्दाम को खत्म किया और इराक को एक प्रकार की अराजक स्थिति में ला दिया।

हालांकि जब जांच रिपोर्ट आई तब मालूम पड़ा की इराक के पास नरसंहारक हितधार थे ही नहीं। हालांकि सद्दाम का शासन भी इराक में लगभग व्यक्ति परक शासन था और उन्होंने अमर्यादित व्यवहार शुरू किया था। इराक में उस होटल के सामने जहाँ विदेशी मेहमान आकर ठहरते थे, सद्दाम ने फर्श पर सीमित जर्जर बूश का चित्र बनवा दिया था ताकि विदेशी मेहमान उनके चित्र पर जूते रखकर निकले। शायद इराकी सरकार और सद्दाम को मिताने का एक कारण यह वैयक्तिक अमर्यादित आचरण भी था जिसका बदला उनके बेटे युश ने राष्ट्रपति बनकर लिया।

अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से लगभग दो-तीन दशक के बाद अमेरिका को पुनः विश्व शक्ति स्थापित करने के नाम पर और अमेरिका के विदेश नीति के छोड़े हुए स्थान को फिर से वापस लाने की योजना में है। इसके लिए उन्हें सामरिक और आर्थिक शक्ति चाहिए। सामरिक शक्ति तो उनके पास है ही परंतु अमेरिका और चीन में आर्थिक समझौते के बाद जिस तरह चीन ने अमेरिकी बाजार पर कब्जा किया था, उसने अमेरिकी आर्थिक क्षमता को घटया था तथा जिन जिन देशों पर अपने नियंत्रण को अमेरिका ने अपने आर्थिक तंगी की वजह से छोड़ा था उन सभी केंद्रों पर अब पुनः अमेरिका की नजर है। अपनी आर्थिक क्षमता को पुनरु स्थापित करने के लिए 'डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले दुनिया के आयातित सामानों पर टैरिफ बढ़ाना शुरू किया है। यह टैरिफ हितधार भी अणु बम से कम खतरनाक नहीं है क्योंकि जो दुनिया के छोटे कमजोर या रीगन देश अमेरिका में अपने माल बेचकर अपनी अर्थ क्षमता को बढ़ा रहे थे और अमरीकी कोष घटना जा रहे हैं।

इस कोष का इस्तेमाल अब अमेरिका अपने वैश्विक जागीरदारी को स्थापित करने और दुनिया के दूसरे देशों की विदेश नीति को नियंत्रित करने में इस्तेमाल कर रहा है। एक बार फिर से अमेरिका उस पुराने दौर में जा रहा है जहाँ वे कहते थे, रबी अमेरिका बम अमेरिकन्या। निस्संदेह इससे अमेरिका का पूंजी विस्तार हुआ है और अब अमेरिका ने इस टैरिफ हितधार के लिए दुनिया के उन देशों की सरकारों को गिराने का माध्यम बनाया है जो उनके अनुकूल नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्था को गिराकर, वहीं विद्रोह करारक अपने हितों के अनुकूल सरकार को बनाया ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जाहिर नीति है।

हालांकि मैं इस बात के लिए ट्रंप की तारीफ करता हूँ कि वे अपने किसी लक्ष्य को छिपाते नहीं है, बल्कि खुलकर कहते हैं। उनकी इच्छ

धी कि उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार मिले और यह उन्होंने खुलकर कहा जिसे एक अर्थ में बेशर्मी भी कहा जा सकता है। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में भी मुद्रा बनाया था कि वे निर्वाचित होने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करायेंगे इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए हालांकि वे अभी तक सफल नहीं हो सके।

पहलामाम आतंकी घटना के बाद जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादी क्षेत्रों पर हमला किया तो, दो तीन दिन के बाद पाकिस्तानी जनरल के प्रस्ताव पर भारतीय सेना के चीफ ने उसे स्वीकार कर, सैन्य हमला रोक दिया। इसको लेकर भी ट्रंप ने लगातार कहा कि भारत पाक युद्ध को मैंने रुकवाया है हालांकि इसे भारत ने नहीं माना और प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया। जब इसके बाद भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो उन्होंने ये कहा शुरू कर दिया है कि अब मैं दुनिया को युद्ध में धकेल कर ही रहूँगा, कोई भी राजनेता जो ये कहता हो इसे उनको बेबाकी भी कहा जा सकता है और अपरिपक्व मूर्खता भी।

वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो का विरोध करने वाली नेता को उन्होंने पुनः समर्थन दिया और शायद वह दुनिया की पहली घटना थी जब दुनिया के किसी देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ रात में अगवा किया गया है और वह भी इस आधार पर कि वे अमेरिका में इस भेजेत है। उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। वेनेजुएला की सरकार भी बदल गई और नई सरकार बन गई। अब जो सरकार है वह अमेरिका के नियंत्रण में है, ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं ही अब वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ।

श्री ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकी दी है और ग्रीन लैंड, कनाडा, डेनमार्क तक को अमेरिका झूड़े में बताया है। एक तरफरूस जिसके मुखिया श्री पुतिन है यूएसएसआर के स्वरूप को और 1985-86 में स्वतंत्र हुए देशों को पुनः अपने कब्जे में लेना का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार अमेरिका भी लैटिन अमेरिकी देशों को जो आजाद हुए थे, पुनः अपने नियंत्रण में लेने की योजना में है। रूस और अमेरिका दोनों अपने-अपने प्रभाव के देशों को कब्जाने की तैयारी में है। अमेरिका अपना कब्जा ग्रीनलैंड पर इसलिए चाहता है कि एक तो वह वहाँ के रियर अंड मिनरल्स का इस्तेमाल करेगा और अपना सामरिक अड्डा वहाँ बनाकर रूस व दुनिया तक को अपनी हितधारियों की सीमा में लेगा।

यूरोपीय संघ जिसके देश अधिकांशतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से फ्रांस में थे अब वे भी अमेरिका के प्रभाव से और तरीकों से चिंतित है। नाटो के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मन चांसलर, ब्रिटेन आदि देश अमेरिका की इन हस्तकों का विरोध कर रहे हैं परंतु वह विरोध कितनी दूर तक जाएगा यह कहना कठिन है। क्योंकि इसाइयत और यहूदी दोस्तों इन्हें एक रास्ते पर ला सकती है।

ईरान और अमेरिका के बीच में भी जो युद्ध का माहौल बना है वह चिंताजनक है। यद्यपि मुझे नहीं लगता की ईरान अमेरिका से कोई सीधे युद्ध की स्थिति में है। पिछले दिनों जब ईरान ने इजरायल पर ड्रोन हमले किए थे, तब अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल छोड़ कर ईरान को लाचार कर दिया था। अभी ईरान प्रह युद्ध में फंसा है एक तरफ खमेनी धर्म गुरु के साथ में कट्टरपंथी समाज है और दूसरी तरफ ईरान का बड़ा हिस्सा संघर्ष में सक्षम पर है। लड़कियां जेल जा रही है और मारी रही है। कई हजार लोग मर चुके हैं और ट्रंप ने तो कहा है कि चिंता मत करो, लड़ो

रहो, मदद रास्ते में है। यह भी ईरान की इस्लामिक सत्ता को हटकर पुनरु शाह की सत्ता और एक खुला समाज बनाने का खेल चला है।

कुल मिलाकर समूची दुनिया अपने छोटे-छोटे युद्धों से आगे बढ़े युद्धों की ओर जा रही है, कट्टरपंथी घटनाये बढ़ रही है। भारत के पड़ोस के बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता और समाज में घूर्णतः हवाही हो चुका है। एक प्रकार की अराजकता की स्थिति है। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है और वे भयभीत है। उनकी स्थिति की कल्पना कर पाते भी कठिन है। हालांकि यह चिंताजनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें उनके समूह के लोग विश्व नेता कहते है, इन छोटे देशों में भी कुछ हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने औपचारिक रूप से अब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याओं पर कुछ नहीं बोला है। हिंदू हितों के रक्षा के आधार पर बनाए गए आरएमएसएर और उनके मुखिया भी लगभग मौन ही है। भारत के अनेकों हिंदू लोग इससे क्षुब्ध है क्योंकि वे अब तक मानते थे कि आरएमएसएर उनके रक्षा के लिए बना है और उन्हें लगत था कि शायद संघ के लोग अपने लाखों स्वयंसेवक के साथ बांग्लादेश कूच करेंगे और हिंदुओं को रक्षा करेगे परंतु, संघ और उसकी नियंत्रित सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा में सफल सिद्ध नहीं हुई। विरोध के नाम पर रास्ट्रवत् के नाम विरोध पत्र देने तक ही सीमित रहेंगे।

दुनिया में प्रबुद्ध लोगों में बहुत चिंता है की क्या दुनिया तोसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है और अगर तोसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये बंदूकों और मिसाइलों का नहीं होगा बल्कि परमाणु बमों का होगा। ऐसे युद्ध मानवता और सभ्यता दोनों को नष्ट कर देंगे।

मालवा गांधी को याद आता दुनिया कर रही है कि गांधी का मार्ग अपनाकर ही युद्धों से बचा जा सकता है। लोहिया ने आज से लगभग 70 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के ललितपुर के घंटा घर में भाषण देते हुए कहा था की बीबीवी सदी की 2 घटनाये महत्वपूर्ण है, एक एटम और दूसरे गांधी। देखते हैं किसकी जीत होती है।

लोहिया ने दुनिया के समक्ष यह प्रश्न रखा था कि गांधी की जीत का मतलब अहिंस की, मानवता की और सभ्यता की जीत था। और अणु और परमाणु की जीत का मतलब मानवता और सभ्यता का नष्ट होना है। अब दुनिया को चुनना है कि वह जीवित रहना चाहती है या समाप्त होना।

इसलिए लोहिया ने विश्व संसद का सुझाव दिया था और वे खुद को विश्व नागरिक कहते थे। गांधी ने खुद को विश्व का पर्याय बना दिया था। कुछ भिन्न इस पर प्रश्न चिह्न लगते है कि इस विश्व स्थिति के रहते विश्व संसद कैसे बनेगी? उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के शोषित और रीगन देश, जिनकी संख्या सौ से अधिक है जिनकी आबादी छह अरब के पास है अगर एक हो जाए तो ये परमाणु वाले देश क्या करेंगे।

बड़े देश अगर परमाणु से दुनिया को खत्म करना चाहेंगे तो बगीर प्रजा के राज होंगे। जब जनता ही नहीं रहेगी तो राज किस पर करेगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि गांधी का संदेश और लोहिया की योजना और रणनीति ही युद्ध, हितधार और शोषण से मुक्ति दिला सकती है।

30 जनवरी बाबा का बलिदान दिवस था। देखें दुनिया बापू के उस महान अहिंसक बलिदान को किस रूप में याद करती है।

आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

आम बजट 2026

प्रमोद भार्गव

लेखक पत्रकार हैं।



नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आथकर की सारिणी में छूट और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोक-तुभावन बजट होगा।लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। जिसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनायाद रख दी है।इस समय भारत उद्योग, प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। क्योंकि इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं।

अमेरिका की निगाहें वेनेजुएला के तेल, डेनमार्क के ग्रीनफील्ड और आर्कटिक के दुर्लभ खनिजों पर टिकी हैं। चीन और रूस आर्कटिक क्षेत्र में खनिज उत्खनन में लग गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के लिए हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों

के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंगरंग राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र,खेलकूद सामग्री, जैविक दवाओं, कटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स, के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है।

रसायन पार्क विकसित होंगे।सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरुआत की जाएगी। चूँकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के

चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी। यहीं वे खनिज हैं, जो क्वार्टम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और अंतरिक्ष उपकरणों में काम आते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अनरगल टैरिफ के बाद चीन ने भारत को उपरोक्त खनिज देने का वादा किया हुआ है।हालांकि ईयू से समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों के आयात-निर्यात का दायरा विस्तृत हो गया है। भारत ने अब खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया हुआ है। क्योंकि भारत की धरती पर इस नजरिए से प्रचुर



उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है। इस दृष्टि से यह उत्पादन और निर्माण के ढांचागत विकास को स्थापित करने का महाबजट है।

दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा हेतु संसद के मानसून सत्र में माईस और मिन्सल्स संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस नए कानून से व्यवसायियों को लौज पर खनन करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लीथियम, कोबाल्ट, निकल, हीरा जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा भी मिल गई है। भारत इन खनिजों के लिए अब तक

मात्रा में धरती के गर्भ में हर तरह के खनिज मौजूद हैं। इसीलिए भारत अब अपनी शतों पर विकसित देशों के साथ व्यापार भी करेगा। इस बजट से इस व्यापार को मजबूती मिलेगी।

ओडिशा, केरल,आंध्र,राजस्थान,जम्मू-कश्मीर और मध्यप्रदेश की धरती के गर्भ में खनिजों का खजाना भरा पड़ा है। इसके दोहन के लिए उद्योगपति बेकरार हैं। लेकिन पर्यावरणीय अड़चनों के कारण पूंजीनिवेश से बचते हैं। लेकिन अब माईस और मिन्सल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की

धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कच्ची में चूने के भंडार हैं। राइडेल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइट, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइट और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं। मध्यप्रदेश में ईंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जलजल पर सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है।

इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा।सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं।सात द्रुत गति के लेन गलियारें बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे।छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे।इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा।इससे स्थानीय लोगों को कर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे। एक जिला.एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है।साफ है यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है।यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आणगे। जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती देंगे, बल्कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।

तंत्रय

राजेंद्र बज

लेखक व्यंग्यकार हैं।



स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धी परिसर, प्रेस कॉमप्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बजट को लेकर एक प्रतिक्रिया कुछ ऐसी भी...

आलसी अपने को ईश्वर का सच्चा पुत्र मानता है। काम या परिश्रम करके वह पालनहार परमपिता की महिमा पर बड़ा नहीं लगाना चाहता है। वह आलस्य के आनंद रस में इतना पगा होता है कि उसे निष्क्रिय जीवन वरदान लगता है। वह सर्वज्ञानी होता है। उसे नया पुराना कुछ भी करने या सीखने की जरूरत महसूस नहीं होती है। असल में वह बंद गोदाम के आखिरी कोने में सहजा हुआ बुद्धिजीवी होता है। उसे अच्छी तरह से पता है कि जीवन चार दिनों का है, ओल्नी फॉर फोर डेज, यू नो ! ना यहां कुछ लेकर आए थे ना यहां से कुछ लेकर जाएंगे।

देना आवश्यक समझते हैं। बजट के चलते कब, कहां और किस पर गाज गिरेगी? अब यह तो जग जाहिर बात है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो हर हाल में खरबूजे को ही होता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक हर साल बड़ी और छोटी सरकारों का बजट आया। लेकिन जिसने जैसा सोचा था, उसने वैसा नहीं पाया। रही बात वास्तव में विकास की, तो इस विकास को बहुत आसानी के साथ आंकड़ों की सहायता से लोगों के गले उतारा जा सकता है। और हां, यदि बात महंगाई और बेरोजगारी की हो, तो इसके उछाल को भी आंकड़ों की ही सहायता से सिद्ध किया जा सकता है।

विद्यार्थी जीवन में जब हमारा सामना सांख्यिकी के सिद्धांत से हुआ, प्रारंभिक प्रस्तावना में ही हमने जान लिया कि समक झूठ बोलते है। इसकी सहायता से जो चाहे वह सिद्ध किया जा सकता है। वैसे भी हर साल बजट को लेकर लोग बाग वैचारिक अटकलें लगाते हैं। इससे ऐसा होगा या इससे वैसा होगा, लेकिन होता वही है जो होना होता है। वैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब-जब बजट आता है महंगाई की हवा आंधी और तूफान के साथ बहने लगा करती है। ऐसे में आम आदमी बेचारीगी में अपनी जेब में पड़ी मुद्रा के अवमूल्यन का दर्श भुगतने की बाध्य हुआ करता है।

अब चूँकि ताजा बजट आ चुका है।

इधर वाले और उधर वाले पहले ही से मांडा सूत कर तैयार बैठे थे। बजट की तारीफ सस्तापत्थर को नुमाईदे मैदान में उतर गए हैं। उनके लिए बजट को वास्तव में समझना कतई आवश्यक नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन्हें केवल और केवल तालियां ही बजाना है। और विरोधी खेमों को छलती ही पीटना है, जिसे पीटना एक प्रकार से उनकी राजनीतिक चेतना का सूचक माना जाएगा। जिसके चलते उनकी राजनीतिक जड़ों को खाद और पानी मिल सकेगा। जनता जनार्दन के बीच भी यह संदेश जाएगा कि कोई है जो उनके सुख-दुख की चर्चा में भागीदार बना हुआ है।

हालांकि जब-जब भी बजट आता है

वितीय मामलों के जानकार उसकी साधिका व्याख्या करते हैं। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में होता आया है। कभी-कभी इन टिप्पणियों में राजनीतिक पूर्वाग्रह की झलक मिलती है। इसलिए इधर का या उधर का पक्ष लेने से बाज नहीं आते। ऐसी स्थिति में जन साधुकरण के लिए अपनी राजनीतिक धारणा के अनुरूप बजट पर टिप्पणी में आसानी हुआ करती है। जिसके चलते चार लोगों के बीच प्रस्तुत बजट का अच्छा खासा विश्लेषण कर अपनी बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ी जा सकती है। आमतौर पर होटल या पान की दुकान पर राजनीतिक विषय पर गपशप करते हुए बजट की समीक्षा करने का अचना एक अलग ही आनंद होता है।

विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।



प्रकृति जीवों-पादपों की पोषक है, सांसों का स्पंदन है। प्रकृति की रचना में जीवन का सौंदर्य एवं लास्य नर्तन है। ऊंचे उठे नभ छूते गिरि शिखरों पर हिम की रजत चादर हो या पर्वतों से जीवन धारा बन निकली बलखाती चंचल सरिताएं हों। तमाम पशु-पक्षियों एवं मानव को भोजन, आश्रय एवं जीवनोपयोगी संसाधन भेंट करते समृद्ध कानन हों या सतत गर्जना करते उताल लहरों से लोक को नाना प्रकार के रत्नों के उपहार बांटते रत्नाकर महासागर हों। पशु-पक्षियों की क्षुधा मिटाते घास के विस्तीर्ण मैदान हों या फिर नागफनी जैसे कंटोले पौधों के रंग-बिरंगे फूलों से सजा रंगिस्तान। प्रकृति की यह वैविध्यपूर्ण बनावट धरती में जीवन गढ़ती है, रचती है। नदी, झील, डेल्टा, घाटी, जल, जंगल, पर्वत, पठार, उदधि, उपवन, रेत, खेत इन सभी में सौंदर्य बिखरा पड़ा है जो मानव मन को आकर्षित करता है। लेकिन प्रकृति की तमाम अद्भुत रचनाओं में से एक रचना पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, हम उसके महत्व एवं पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका से सर्वथा अपरिचित हैं और वह अप्रतिम प्राकृतिक संरचना है आर्द्रभूमि अर्थात् धरती का नमी वाला क्षेत्र। वायुमंडल में जलवाष्प की उपलब्धता, आंभी-तूफान और सागरीय चक्रवात, वर्षा एवं वायु विशोधन आदि का आधार भूमि की आर्द्रता ही होती है, यह हममें से बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आर्द्रभूमि के महत्व एवं योगदान से परिचित कराने हेतु वैश्विक आयोजन प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस के रूप में किया जाता है। रामसर सम्मेलन में हुई संधि की 55वीं वर्षगांठ हम 2026 में मना रहे हैं।

इसके पहले कि मैं आर्द्रभूमि दिवस मनाने के उद्देश्यों, जीवों-पादपों के जीवन चक्र पर आर्द्रता के पड़ने वाले प्रभावों एवं पारिस्थितिकी तंत्र की बनावट-बसाहट पर

आर्द्र भूमियों पर पनपती है समृद्ध जैव विविधता

बात करूँ, मुझे लगता है कि आर्द्रभूमि को समझना समीचीन होगा। आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र अंतर्गत धरती का वह विशेष क्षेत्र होता है जो आंशिक या पूर्णतः वर्ष भर, न्यूनतम आठ महीने, प्रायः जल में डूबा रहता है

और जहां जलीय पादपों एवं जल-जीवों की तमाम प्रजातियां विकसित होकर इको सिस्टम को समृद्ध करती हैं। एक प्रकार से भरपूर नमीयुक्त यह दलदली भूभाग जलीय एवं स्थलीय जैव विविधता का मिलन बिंदु या संधि क्षेत्र होता है। दुर्भाग्य से मानवीय दखल एवं हस्तक्षेप से सम्पूर्ण विश्व में आर्द्रभूमि पर संकट उभरा है जो न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे जीव-पादप विकास एवं जैव जीवन पर खतरा बनकर मंडरा रहा है, क्योंकि आर्द्रभूमि का खत्म होना या क्षेत्र कम होना पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक चक्र को अस्थिर कर देगा और तब तमाम जीव-पादप प्रजातियां विलुप्त हो जायेंगी। इस दृष्टि से विचार करके 2 फरवरी, 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर नगर में आर्द्रभूमि के संरक्षण, युक्तिसंगत उपयोग एवं तत्संबंधी वैश्विक जागरूकता के लिए आयोजित सम्मेलन में एक समझौता हुआ जिसे रामसर संधि कहा जाता है। जिसमें कहा गया कि प्रत्येक देश अपने यहां नेचुरल वेट लैंड अर्थात् प्राकृतिक आर्द्रभूमि को चिह्नित करेगा। ऐसे चिह्नित सभी स्थल रामसर साइट कहे जायेंगे और उनकी एक समग्र वैश्विक सूची बनाई जायेगी। वर्तमान समय में इस सूची में 172 देशों की 2530 से अधिक आर्द्र भूमियों का अंकन किया गया है। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक रामसर साइट यूनाइटेड

किंगडम में हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमरीकी देश बोलिविया शीर्ष पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एवरग्लेड्स वेटलैंड विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट है। इसके साथ ही इन सूचीबद्ध रामसर आर्द्रभूमियों में से

रूप में पहचाना गया। रामसर सम्मेलन के 26 साल बाद 2 फरवरी, 1997 को पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया।

रामसर संधि के तहत समुद्र स्तर से 6 मीटर ऊंचा



ऐसे स्थल जो मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण एवं तकनीकी विकास के कारण बड़े बदलावों का शिकार हुए या हो रहे हैं, उन्हें मॉट्रिक्स रिकार्ड नामक एक पंजीक में अंकित कर संरक्षण के विशेष प्रयास किये जाने हेतु योजना बनाई गयी है और सरकारी एजेंसियों एवं पर्यावरण मुद्दे पर केंद्रित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा योजनानुसार संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। मॉट्रिक्स रिकार्ड सूची में भारत के दो आर्द्र स्थल शामिल हैं। वर्ष 1990 में केवलादेव घना पक्षी बिहार, भरतपुर (राजस्थान) तथा 1993 में लोमतक झील मणिपुर को संकटग्रस्त रामसर साइट के

ज्वार-भाटा आच्छादित तटीय क्षेत्र एवं गहरे धान क्षेत्र, डेल्टा, झीलें आदि आर्द्र भूमि अंतर्गत शामिल हैं। विश्व की एक अरब आबादी का जीवन यापन आर्द्रभूमि पर ही निर्भर है। वहीं भूमि आधारित कार्बन के 30 प्रतिशत हिस्से का स्रोत भी यही वेट लैंड साइट ही है। आर्द्र भूमियों के महत्व को हम यूनेस्को के एक कथन से समझ सकते हैं कि आर्द्रभूमि पर खतरा उत्पन्न होने से विश्व की 40 प्रतिशत वनस्पतियां एवं जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो इन आर्द्र भूमियों पर पाये जाते हैं और प्रजनन करते हैं। विश्व की भू सतह का 6 प्रतिशत हिस्सा आर्द्रभूमि है। भारत 98 रामसर साइट के साथ एशिया में प्रथम स्थान पर है। ये आर्द्रभूमि लगभग तेरह लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र को आच्छादित करती हैं। इनमें चिल्का झील उड़ीसा, नंगल एवं रोपड़ वेटलैंड पंजाब, भिंडावास अभयारण्य हरियाणा, कांवर झील बिहार, अष्टमुड़ी केरल, दीपोर आर्द्र भूमि असम, सांभर झील राजस्थान, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर पक्षी बिहार, राजस्थान), स्तार्ती सापुक लद्दाख, भोज आर्द्र भूमि मध्यप्रदेश आदि सहित दो नये साइट

पटना पक्षी बिहार, एटा उत्तर प्रदेश तथा छारी बांड कच्छ गुजरात को वर्ष 2025 में ही इस सूची में शामिल किया गया है। इनमें हिमाचल एवं लद्दाख सहित उत्तरी ठंडे एवं शुष्क क्षेत्र, दक्षिण का तटीय क्षेत्र, मानसूनी वन प्रदेश, बाढ़ वाले मैदानी इलाके, डेल्टा एवं झीलें आदि सम्मिलित हैं। 4230 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है तो हिमाचल का रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा मात्र 0.2 वर्ग किमी क्षेत्र है, जिसकी घोषणा 15 अक्टूबर, 2012 को हुई थी। उल्लेखनीय है कि रामसर संधि भारत में फरवरी 1982 से लागू हुई। आर्द्र भूमियों के उचित संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए एक केंद्रीय कानून आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के अंतर्गत सुनियोजित ढांचा विकसित किया गया है। 2 फरवरी, 2021 को आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित कर आर्द्र भूमियों की आवश्यकता, अनुसंधान, संरक्षण एवं सम्बंधित ज्ञान-सूचना को परस्पर साझा करने के ठोस प्रयास शुरू किये गये। वर्ष 2025 के आयोजनों की थीम थी - हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, जबकि 2026 की थीम है- आर्द्रभूमि और पारम्परिक ज्ञान : सांस्कृतिक विरासत का उत्सव।

वास्तव में आर्द्रभूमि जीव-पादप के समुचित विकास का आधार बन जैव विविधता को पुष्टि प्रदान करती है। यहां से कच्चा माल, दवा, वनस्पतियां, आहार आदि की प्राप्ति होती है तो वहीं यह पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने में भी सहायक है। यह कचरे के छानने हेतु प्राकृतिक छानने का काम करती है। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के प्रभाव को कम कर पीने का पानी के स्रोत भी हैं। अति संवेदनशील ये स्थल उन जलीय वनस्पतियों एवं मछलियों को पनपने का अनुकूल परिवेश देते हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इस प्रकार आर्द्रभूमियां एक प्रकार से जीवन को संवतरी-सजाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम भी इन आर्द्र भूमियों को संभालें-संवारें और आगामी पीढ़ी को समृद्ध जैव विविधता पूर्ण खिली-महकती दुनिया सौंपें।

दृष्टिकोण

अनुपमा तिवारी

लेखक जयपुर निवासी शिक्षाविद व ट्री गुमन ऑफ राजस्थान हैं।



यह सच है कि हम सब अपने माता - पिता से शरीर प्राप्त करते हैं और फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था प्राप्त करते हुए प्रौढ़ होते हुए वृद्ध हो कर जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हैं ठीक इसी प्रकार पेड़ - पौधे बीज से पैदा होते हैं, बड़े हो कर फूल - फल देते हैं और फिर अपनी निश्चित आयु के बाद खत्म हो जाते हैं। फूलों और फलों के परिपक्व होने के बाद बीजों से नए पौधे जन्म लेते हैं जैसे हम युवावस्था में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। प्रत्येक फल का पौधा, बीज से बड़ा होते हुए जब किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद युवावस्था में जाता है तो शुरुआत में उसमें पहले 2-3 फल ही आते हैं उसके बाद अगली फसल में 20-25 फल लगते हैं और उसके बाद की अगली फसलों में भरपूर फल लगते हैं। इसी प्रकार कोई लड़की जब किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसे पहली बार मासिक धर्म अनियमित मात्रा में और कम - ज्यादा दिनों का होता है और फिर एक - दो महीनों के बाद वह नियमित हो जाता है।

हमारी दुनिया

ब्रजेश कानूनगो

लेखक संभारक हैं।



जि स तरह अफ्रीका महाद्वीप की जेब्रा, जिराफ, चिंपाजी और शेर से, अंटार्कटिका की पेंग्विन, सील और व्हेल से, उत्तरी ध्रुव प्रदेश की भालू से, अरब और रंगिस्तान क्षेत्र की ऊंटों से पहचान बनती है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पहचान कंगारू से बनती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय पशु है। यह अपने खास चलने के अंदाज और बच्चों को रखने वाली थैली के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है।

प्राकृतिक रूप से कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यह दुनिया के अन्य किसी भी महाद्वीप (जैसे एशिया, अफ्रीका या अमेरिका) में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। करोड़ों साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया अन्य महाद्वीपों से अलग हुआ, तो यहाँ के जीव बाकी दुनिया से कट गए। कंगारू एक 'मार्सुपियल' (Marsupial) यानी धानीप्राणी है, और इस प्रजाति का विकास इसी भौगोलिक अलगाव के कारण ऑस्ट्रेलिया में हुआ।

कंगारू जैसे अपने विशिष्ट जीव वाले देश की पहचान के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अपने यहां के ऊंटों के कारण भी बहुत चर्चा में बना रहता है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि आज सऊदी अरब और कतर जैसे देश, जहाँ ऊंटों की बहुत अहमियत है, ऑस्ट्रेलिया से ऊंट आयात करते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं पहला यह कि ऑस्ट्रेलिया के ऊंट रोग-मुक्त और पूरी तरह 'ऑर्गेनिक' होते हैं, इसलिए उनके मांस की मांग अरब देशों में बहुत है। दूसरा कारण है कि ऑस्ट्रेलियाई ऊंटों की शुद्धता और मजबूती के कारण, इनका उपयोग वहाँ की नस्लों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।

अरब और भारत के ऊंटों से इनके अलग होने के कुछ विशिष्ट कारण हैं। मध्य पूर्व और भारत के ऊंट अक्सर कई बीमारियों (जैसे 'सरा') से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊंट दुनिया के सबसे स्वस्थ ऊंट माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे एक सदी से भी अधिक समय तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहे, जिससे उन तक संक्रामक बीमारियाँ नहीं पहुँचीं। चूँकि ये ऊंट जंगली हैं, इन्हें

प्रकृति को जानेंगे तो जीवन को बेहतर समझेंगे

इसी प्रकार यदि किसी बेल में खूब खाद - पानी डाला जाए तो वह जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, उस में फूल भी आ जाएँगे लेकिन फल नहीं लग पाएँगे या लगे तो झड़ जायेंगे या उत्तम गुणवत्ता वाले नहीं होंगे ठीक उसी तरह यदि किसी लड़की को खूब - खिला पिला कर उसे बड़ा करने की हम कोशिश करें तो मासिक धर्म के बाद वह गर्भवती तो हो सकती है लेकिन या तो उसका गर्भपात हो जाएगा या वह जिस बच्चे को जन्म देगी वह काफी हद तक स्वस्थ नहीं होगा। फल और फूल देने की प्रत्येक पौधे की एक निश्चित आयु होती है वह जीवनभर फूल या फल नहीं देता है वह खाद - पानी पा कर एक निश्चित आयु तक जीवित रह सकता है। ठीक इसी प्रकार एक-नीवू का पेड़ लगभग 15 वर्ष तक फल देता है, उसके बाद वह फल नहीं देता है लेकिन वह जीवित रहता है जैसे एक महिला लगभग 45-50 की आयु तक बच्चे पैदा कर सकती है और मेनोपोज के बाद वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती लेकिन वह जिंदा रह सकती है।

बरगद/बड़ का पेड़ बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है और अधिक आयु तक जीवित रहता है ठीक उसी प्रकार कछुआ अंडे से काफी समय के बाद निकलता है और फिर धीरे-धीरे बढ़ता है और अधिक आयु तक जीवित



रहता है. जो पौधा जितनी जल्दी बढ़ता है वह अपना आयु चक्र भी उतनी ही जल्दी पूरा कर लेता है. पपीते का पेड़ बीज से फल तक के चक्र को 9 से 12 महीने में पूरा करता है इसलिए उसकी आयु भी कम (तीन वर्ष तक) की ही होती है.

एक मनुष्य का बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है और एक हथिनी 27 महीने तक गर्भवती रहती है। मनुष्य की आयु औसतन 70-80 साल होती है तो हाथी की आयु लगभग 150 से 210 वर्ष के आस - पास तक होती है. मच्छर अपने अंडे में से निकलने के बाद लगभग तीन दिन ही जीवित रहता है. अंडे से मच्छर के बाहर निकलने का समय बहुत कम है तो उसका जीवन भी कम समय का है. हम यदि अपने जीवन की भी जानना और समझना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए उसे देखना और सुनना चाहिए. वह बहुत सहज और सरल है। उसमें एक प्रवाह है। वह हमें बहुत कुछ सिखाए और समझा सकती है. बस, उसे देखने - सुनने के लिए आँख व कान और महसूसने के लिए दिल चाहिए. जब हम प्रकृति को महसूसते हैं तो अपना जीवन हम और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं.

कंगारू के देश में ऊंटों का जलवा

कंगारू जैसे अपने विशिष्ट जीव वाले देश की पहचान के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अपने यहां के ऊंटों के कारण भी बहुत चर्चा में बना रहता है। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि आज सऊदी अरब और कतर जैसे देश, जहाँ ऊंटों की बहुत अहमियत है, ऑस्ट्रेलिया से ऊंट आयात करते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं पहला यह कि ऑस्ट्रेलिया के ऊंट रोग-मुक्त और पूरी तरह 'ऑर्गेनिक' होते हैं, इसलिए उनके मांस की मांग अरब देशों में बहुत है। दूसरा कारण है कि ऑस्ट्रेलियाई ऊंटों की शुद्धता और मजबूती के कारण, इनका उपयोग वहाँ की नस्लों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। अरब और भारत के ऊंटों से इनके अलग होने के कुछ विशिष्ट कारण हैं। मध्य पूर्व और भारत के ऊंट अक्सर कई बीमारियों (जैसे 'सरा') से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊंट दुनिया के सबसे स्वस्थ ऊंट माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे एक सदी से भी अधिक समय तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहे, जिससे उन तक संक्रामक बीमारियाँ नहीं पहुँचीं। चूँकि ये ऊंट जंगली हैं, इन्हें भोजन और पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है। इस कारण ये पालतू ऊंटों की तुलना में अधिक मांसपेशी युक्त (Muscular) और ताकतवर होते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की सबसे शुद्ध 'ड्रोमेडरी' (एक कूबड़ वाली) नस्ल पाई जाती है, क्योंकि वहाँ इनका अन्य प्रजातियों के साथ संकरण (Cross-breeding) नहीं हुआ।

भोजन और पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है। इस कारण ये पालतू ऊंटों की तुलना में अधिक मांसपेशी युक्त (Muscular) और ताकतवर होते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की सबसे शुद्ध 'ड्रोमेडरी' (एक कूबड़ वाली) नस्ल पाई जाती है, क्योंकि वहाँ इनका अन्य प्रजातियों के साथ संकरण (Cross-breeding) नहीं हुआ।

पालतू ऊंट आमतौर पर शांत होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगली ऊंट इंसानों के प्रति बहुत सतर्क और कभी-कभी आक्रामक होते हैं। ये ऊंट बहुत बड़े झुंडों में रहते हैं (कभी-कभी सैकड़ों की संख्या में), जबकि पालतू ऊंटों को छोटी टोलियों में रखा जाता है। सूखे के समय ये हजारों की तादाद में एक साथ पानी की तलाश में निकलते हैं, जो एक डरावना दृश्य होता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में पानी बहुत खारा होता है यहाँ के ऊंटों ने उच्च लवणता (Salinity) वाला पानी पीने की क्षमता विकसित कर ली है, जो सामान्य पालतू ऊंटों के लिए घातक हो सकता है। ये ऊंट ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय कैंटीली झाड़ियों और उन पौधों को भी खा जाते हैं जिन्हें वहाँ के स्थानीय जानवर (जैसे कंगारू) नहीं खा सकते।

ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों का इतिहास और वर्तमान स्थिति काफी अनोखी है। जहाँ दुनिया के कई हिस्सों में ऊंट पालतू जानवर के रूप में पाए जाते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये 'जंगली' (Feral) हो चुके हैं और पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते थे। सबसे पहले 1840 में कैनरी आइलैंड्स से ऊंट ऑस्ट्रेलिया लाए गए। इसके बाद 1860 से 1907



स्थिति काफी अनोखी है। जहाँ दुनिया के कई हिस्सों में ऊंट पालतू जानवर के रूप में पाए जाते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये 'जंगली' (Feral) हो चुके हैं और पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते थे। सबसे पहले 1840 में कैनरी आइलैंड्स से ऊंट ऑस्ट्रेलिया लाए गए। इसके बाद 1860 से 1907

के बीच भारत और अफगानिस्तान से हजारों ऊंट आयात किए गए।

विशाल रंगिस्तानी इलाकों की खोज, सामान ढोने, और रेलवे व टेलीग्राफ लाइनों के निर्माण के लिए ऊंट सबसे उपयुक्त थे क्योंकि वे घोड़ों से अधिक सहनशील थे। इनके साथ ऊंट हांकने वाले अफगान लोग (Cameleers) भी आए। जब मोटर गाड़ियाँ और ट्रैक आ गईं, तो ऊंटों की जरूरत खत्म हो गई। कई मालिकों ने इन्हें रंगिस्तान में खुला छोड़ दिया। अनुकूल वातावरण और शिकारियों की कमी के कारण इनकी आबादी तेजी से बढ़ी। आज ऑस्ट्रेलिया में जंगली ऊंटों की संख्या 10 लाख से भी अधिक होने का अनुमान है, जो हर 8-9 साल में दोगुनी हो जाती है। इनके कारण अनेक समस्याएँ पैदा हो रही हैं। ये ऊंट एक बार में सैकड़ों

लीटर पानी पी सकते हैं। सूखे के दौरान, पानी की तलाश में आदिवासी बस्तियों में घुस जाते हैं, पक्षपलाइन तोड़ देते हैं और एयर कंडीशनर तक से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। ये मवेशियों के लिए लगाई गई बाड़ (fences) और पानी की टँकियों को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। देशी वनस्पतियों को खा जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव

(Erosion) बढ़ता है। वे शुद्ध जल स्रोतों (Waterholes) को भी गंदा कर देते हैं, जिससे स्थानीय जीव और पौधे मर जाते हैं। ऊंट बड़ी मात्रा में मीथेन गैस छोड़ते हैं, जो ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार और स्थानीय समुदाय ऊंटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े और विवादास्पद कदम उठाते हैं, जैसे हवाई शूटिंग (Aerial Culling) सबसे प्रमुख तरीका है। हेलीकॉप्टरों से पेशेवर निशानेबाज जंगली ऊंटों को मारते हैं ताकि उनकी संख्या कम की जा सके। एक जानकारी के अनुसार 2020 के भीषण सूखे के दौरान लगभग 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश दिया गया था। कुछ ऊंटों को पकड़कर उनका मांस (Meat) निर्यात किया जाता है या उन्हें पालतू बनाकर पर्यटन (केमल सफारी) में इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया अब मध्य पूर्व के देशों को ऊंट निर्यात भी करता है, क्योंकि वहाँ ऊंटों की नस्ल और मांस की मांग है। इनके आतंक से बचने के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोतों और संवेदनशील इलाकों के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाई जाती है ताकि ऊंट वहाँ पहुँच कर नुकसान न पहुँचा सकें।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के जंगली ऊंटों ने पिछले 100-150 वर्षों में खुद को वहाँ के वातावरण के अनुसार इस तरह ढाल लिया है कि वे अब अपने पूर्वजों (मध्य पूर्व और भारत के ऊंटों) से काफी अलग दिखाई और व्यवहार करते हैं। यह बात भी बहुत दिलचस्प है कि कंगारू प्रधान देश में ऊंटों की इतनी अधिक संख्या है कि वहाँ प्रतिवर्ष ऊंटों की दौड़ (Camel Racing) का आयोजन भी किया जाता है, जो काफी लोकप्रिय है।

भाजपा नेताओं ने सराह केन्द्रीय बजट सभी वर्गों को मिली प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करता बजट - विधायक, नीना वर्मा



धारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर जिले में उत्साह का माहौल रहा। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती के नेतृत्व में जिले के सभी मंडलों व प्रमुख स्थानों पर बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। इसी क्रम में भाजपा जिला कार्यालय धार व विधायक नीना वर्मा, डॉ. शरद विजयवर्गीय भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, जिला टोली सदस्य मोहित तातेड़, डल अध्येक्ष विशाल

निगम ने भाजपा कार्यकर्ता व्यापारी के साथ केन्द्रीय बजट को सुना।

भाजपा नेताओं ने बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सभी वर्गों-युवा, महिला, किसान, व्यापारी व गरीब-के कल्याण के साथ देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाला ऐतिहासिक है।

यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला समावेशी बजट है - नीलेश भारती जिला अध्यक्ष- भाजपा जिला अध्यक्ष महंत भारती ने बताया कि विश्वास पर आधारित

विकास का बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बजट। यह आने वाले 10 वर्षों में भारत की दिशा तय करने वाला है। यह बजट हर वर्ग-किसान, युवा, महिला, उद्योगपति व व्यवसायी-को राहत देने वाला समावेशी बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। विधायक नीना वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करता बजट है। यह बजट भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी, जिला पदाधिकारी अमृत जैन, राखी राय, मनीष प्रधान, सोनू रघुवंशी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री अंकित भावसार, मंडल महामंत्री अमित शर्मा, डॉ. शैलेन्द्र तिवारी, कालीचरण सोनवानिया, बादल मालवीय, देवेंद्र रावल, सन्नी होड़, प्रतिभा शर्मा, मंजुला बघेल, अनुसुइया वैष्णव, अल्पना जोशी, डाली जाधव समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रतापभानु सिंह चौहान स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस मंडीदीप, सोहागपुर ने विजयश्री हासिल की

सुबह सवेरे सोहागपुर।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रताप भानु सिंह स्मृति चौहान अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के 61 में साल की प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय के खेल मैदान में हकी के चार मुकाबले हुए। जिसमें मंडीदीप तथा सोहागपुर टीम की जीत हुई। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अतिथियों ने टीम पर इनाम घोषित किए। प्रतियोगिता के द्वितीय दिन का खेल पंडित प्रकाश मुद्दल जी, नगर पालिका अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, सिंचाई विभाग के एसडीओ अजय सिंह जी, महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष कैलाश पालीवाल, कानूनाल अग्रवाल, सचिव हमीर सिंह चंदेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अभिलाष सिंह चंदेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष मालवीय आदि के आतिथ्य में संपन्न हुआ। द्वितीय दिन का पहला मुकाबला मंडीदीप बनाम बैतूल के बीच खेला गया। जिसमें मंडीदीप की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैतूल को 3-0 से पराजित किया। दूसरा मैच में हरदा ने इटारसी को 2-0 से हराकर जीत दर्ज की। तीसरे



मुकाबले में भोपाल की टीम ने कड़े संघर्ष में ट्राई ब्रेकर में होशंगाबाद को मात दी। चौथी प्रतियोगिता में सोहागपुर एवं नावापारा टीम के मध्य हुआ। जिसमें सोहागपुर टीम ने अपने कौशल से उत्तर प्रदेश की नानापारा टीम को ट्राई ब्रेकर में जबरदस्त पराजित किया। निर्णायक रवी हरदुआ एवं शिवम सोनोधीया थे। इस अवसर पर आयोजन समिति अध्यक्ष जयराम रघुवंशी, भानूप्रकाश

तिवारी, शेर खान, जयप्रकाश माहेश्वरी, संजय खंडेलवाल, सचिव पवन सिंह चौहान, संयोजक अश्वनी सोरोज, शंकरलाल मालवीय, अभिषेक चौहान, सौरभ तिवारी, अभिनव पालीवाल, दादराम कुशवाहा, एकम राजपूत, दिलीप परदेशी, अंकुश जायसवाल, शेख आरिफ, किशोर काका, मनोज गोलाणी, दीपक तिवारी, अनुज जायसवाल आदि उपस्थित थे।

90कोणीय रास्ते में होते रहते हैं हादसे

ग्राम लांगाबम्होरी के पास शिफ्ट कार 90 कोणीय रास्ते में गिरी एक की मौत

सोहागपुर। भोपाल से पचमढ़ी जाते सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम लांगाबम्होरी के पास 90 कोणीय ब्लैक स्पॉट पर शिफ्ट कार खाई में गिर गई। इस कार में भोपाल के चार युवक अंशुल प्रजापति, दीपक अहिरवार, रोहित कटारे एवं आकाश साहू सवार थे। उक्त कार 90 कोणीय रास्ते में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में आकाश साहू पिता हरिप्रसाद साहू की कार में दबने से मृत्यु हो गई।



पुलिस ने पंचनामा के बाद परिजनों को सौंपा दिया। पुलिस ने मामला कायम कर जांच में लिया है। उल्लेखनीय है कि सोहागपुर विधानसभा के मुख्यालय सोहागपुर के समीपवर्ती ग्राम लांगाबम्होरी के 90 कोणीय के मोड़ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ज्ञातव्य है कि विगत वर्षों पूर्व एक बस दुर्घटना हुई थी। जिसमें करीबन 15 से अधिक यात्रियों की मौतें हो गई थी। तब जोर शोर से कहा गया था कि कुछ ही दिनों में 90 कोण बिलेक स्पॉट

के रास्ते को सीधा करवा दिया जाएगा। ताकि नागरिकों का जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन यह दूर की कोढ़ी सिद्ध हुआ है। नागरिक अब भी लांगाबम्होरी के सीधे रास्ते बनने की राह देख रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इस 90 कोणीय ब्लैक स्पॉट पर आए दिन जो हादसे होते रहते हैं। इन हादसे में अधिकांश हादसे अन्य नगरों के वाहन होते हैं। जिसमें वाहन चालकों को यह अंदाशा ही नहीं हो पाता कि यहां रास्ता कितना खतरनाक है?

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट : हेमंत खंडेलवाल

भाजपा द्वारा आयोजित व्यापारी संवाद में बोले प्रदेश अध्यक्ष

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर के रामकृष्ण बागिया लॉन में आयोजित बजट प्रस्तुतिकरण एवं व्यापारी संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है। वह सिर्फ एक वर्ष का बजट नहीं बल्कि अगले 10 साल में भारत का भविष्य कैसा होगा उसे ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया बजट है। यह बजट देश की दिशा तय करने वाला एवं विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि सुधार, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार देश में तीन नए आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे, मेडिकल टूरिज्म के 5 नए हब बनेंगे। नए टेक्स्टाईल पार्क की स्थापना होगी, 22 नए जलमार्ग प्रारंभ किए जाएंगे एवं 7 हार्ड स्पीड रेल कारिडोर का निर्माण किया जाएगा। छोटे शहरों में स्थित तीर्थ स्थलों को विकसित किया जाएगा। लक्ष्मण दीदीयों की आय बढ़ाने के लिए छोटे छोटे विक्रय केन्द्र खोले जाएंगे।



उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में रोजगार सृजन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आने वाले दशक में भारत वैश्विक निर्माण का सबसे बड़ा केन्द्र बनेगा। पुराने औद्योगिक सेक्टर को जीवित किया जाएगा। मछली पालन के लिए 500 अमृत जलाशय बनाए जाएंगे। डेरी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। विदेश यात्रा सस्ती होगी। पर्यटन को

बढ़ावा देने के लिए बुद्ध सर्किट का निर्माण होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि यह बजट विश्वास और विकास का बजट है। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह बजट देश को नई दिशा देने वाला बजट है। जिसमें सभी सेक्टर एवं समाज के सभी वर्गों के विकास की चिंता की गई है। विधायक डा.योगेश पंडाय ने कहा कि बजट में 5 रिजनल मेडिकल हब बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य पेशावरों के लिए नए संस्थानों का उन्नयन एवं स्थापना का निर्णय भी स्वागत योग्य है। कैसर सहित कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली कई दवाइयों का सस्ता किया गया है। जो निश्चित ही एक राहत देने वाला कदम है। इस बजट का जितना भी स्वागत किया जाए कम है। इस अवसर पर ब्रज कपूर, गजानंद मोटवानी, नवीन तातेड़, प्रेमशंकर मालवीय, श्रीचंद्र हिराणी, मंजीतसिंह साहनी, रमेश मिश्रा, नपाध्यक्ष पार्वती बारस्कर सहित प्रमुख व्यापारी, प्रोफेशनल एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन केन्द्रीय बजट प्रचार अभियान के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने किया एवं अंत में आभार जिला कोषाध्यक्ष दीपक सलूजा ने व्यक्त किया।

'आपरेशन मैट्रिक्स' के तहत म्यूल बैंक खातों के संगठित गिरोह का पर्दाफाश

9 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख नगद बरामद, 13 लाख की राशि फ्रीज, 19 मोबाईल फोन सहित दर्जनों चेकबुक-एटीएम कार्ड बरामद

देवास। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य साइबर सेल मुख्यालय ए.साई मनोहर के निर्देशन पर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 'आपरेशन मैट्रिक्स' की शुरुआत की गई है। इस विशेष अभियान का प्राथमिक लक्ष्य उन संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित कर एजेन्टों तथा किराये पर खाता देने वाले लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करना है, जिनका उपयोग साइबर फ्राड के जरिए लूटी गई रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा है। इस आपरेशन के केंद्र में वे कमीशन पर किराये से लगाये गये खाते हैं, जिन्हें साइबर अपराधी अपनी पहचान छुपाने के लिए ढाल बनाते हैं।



इसी कड़ी में 'आपरेशन मैट्रिक्स' के तहत पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों तथा जिला साइबर सेल देवास को आदेश दिया गया है कि 'आपरेशन मैट्रिक्स' की मंशा के अनुरूप देवास जिले को 'म्यूल अकाउंट' मुक्त बनाया जाना है। जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीरसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास सुमित अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को 'म्यूल अकाउंट' देवास से आपरेट होने की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 08.01.2026 को पुलिस टीम द्वारा होटल 'श्री जी' गंगानगर देवास में तत्काल दबिश दी गई। होटल के एक कमरे में सायबर फ्राड से सम्बंधित पाँच आरोपियों मुनेश्वर उर्फ मनीष सेन, पिपुषु बिल्लोरे, शुभम जोशी, आरोपी जैन उर्फ गोलू व गौरव जैन को अभिरक्षा में लेकर पंछताछ की गई। आरोपीगण से प्राप्त जानकारी और मोबाईल फोन तथा बैंक स्टैटमेंट खंगाले गये तो पाया गया कि मुनेश्वर उर्फ मनीष सेन के दो करंट अकाउंट में करोड़ों का ट्रॉजेंकशन हुआ है। करोड़ों रूपयों के इन ट्रॉजेंकशन का कोई भी स्पष्टीकरण पाँचों आरोपीगण के पास नहीं था।

आरोपीगण ने पुछताछ पर बताया कि

वह सभी पाँचों लोग ऐसे साइबर ठगों के लिये काम करते हैं जो अपनी पहचान छुपाकर टेलीग्राम के जरिये देश के अलग अलग शहरों से सम्बंध रखने वाले भोले भाले लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाभ दिलाने का लालच देकर खातों में करोड़ों रुपये का ट्रॉजेंकशन करवाते हैं तथा रफू चक्कर होकर उनसे दूरी बना लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/2026 थारा 318(4), 316(5) BNS वृद्धि धारा 6(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम का पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण से जप्त सामग्री, बैंक अकाउंट्स, डिटेल्स आदि तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर डिजिटल ट्रेल का पीछा कर इन पाँच आरोपियों के अलावा साइबर ठगों को म्यूल खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 04 सिनियर एजेन्ट्स मंजीत सिंह भाटी उर्फ राज सोनी, नितेश बिरला, जितेंद्र राजपूत उर्फ जितु उर्फ लेफटी व शुभम परमार उर्फ शुब्बु को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपीगण के कब्जे से अभी तक कुल 19 अत्याधुनिक एंड्राईड मोबाईल फोन कीमती करीबन 4,77,000/- रुपये, नगदी 2,00,000/- रुपये, 1 वायफाय बाक्स, 2 चेकबुक, 2 ए.टी.एम.कार्ड, 2 पेन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 नोटबुक, 1

जमापची, 2 सील मुहर तथा घटना में प्रयुक्त एक टाटा नेक्शन कार क्रमांक MP22ZA1009 कीमती करीबन 10 लाख रुपये कुल मश्रुका करीबन 16,77,000/- (सोलह लाख सत्तरहजार रुपये) का मश्रुका जप्त किया गया तथा खातों में सायबर फ्राड से संबंधित करीबन 13 लाख रुपये की धनराशि फ्रीज कराई गई। पुलिस ने अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य संदेहियों के सम्बंध में भी जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर रही है।

जप्त सामग्री
दस्तावेज:- (2 चेकबुक, 2 ए.टी.एम. कार्ड, 2 पेन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 नोटबुक, 1 जमापची)

उपकरण:- 19 अत्याधुनिक एंड्राईड मोबाईल फोन, 1 वायफाय बाक्स व 2 सील मुहर (कीमत लगभग 4,77,000/- रुपये)

धनराशि:- 2 लाख रुपये नगदी तथा साइबर फ्राड से सम्बंधित करीबन 13 लाख रुपये की राशी फ्रीज कराई गई।
वाहन:- टाटा नेक्शन कार क्रमांक MP 22 ZA1009 (कीमत लगभग 10 लाख रुपये)

कुल जप्त मश्रुका: ₹. 29,77,000/- (₹. 16,77,000/- जप्त एवं ₹. 13,00,000/- बैंक खाते में फ्रीज)

गिरफ्तार आरोपी:

- मुनेश्वर उर्फ मनीष पिता लक्ष्मणप्रसाद सेन उम्र 38 साल नि.धर्मपुरा, वार्ड क्र.39 पृथ्वीराज वार्ड, दमोह (म.प्र.)।
- पीयूष पिता अनिल बिल्लोरे उम्र 24 साल निवासी म.नं. 183 विजयश्री नगर थाना एरोडम जिला इंदौर।
- शुभम पिता प्रकाश जोशी उम्र 29 साल निवासी न्यू विज्ञान नगर डाइट रोड जिला टोंक (राजस्थान)।
- आशीष उर्फ गोलू पिता अशोक कुमार जैन उम्र 42 साल निवासी असाटी वार्ड क्र.01 पुराना थाना दमोह (म.प्र.)
- गौरव पिता खुशालचंद्र जैन उम्र 42 साल निवासी जैन मंदिर के पास, वार्ड क्र. 01 मेन रोड, धनोरा जिला सिवनी हाल मुकाम राममनोहर लोहिया वार्ड, अंधेरेदेव जबलपुर (म.प्र.)।
- मंजीत पिता राजू सिंह भाटी उम्र 31 साल निवासी म.नं. 110-ए.नगीन नगर, थाना एरोडम जिला इंदौर।
- नितेश बिरला पिता भागीरथ बिरला उम्र 26 साल निवासी गोवर्धन पैलेस, शिरपुर धार रोड, इन्दौर।
हाल मुकाम म.नं. 58 राधाकृष्णविहार कालोनी एकतानगर, नंदबाग रोड, इन्दौर।
- जितेंद्र उर्फ जितू उर्फ लेफटी पिता सुरेश राजपूत उम्र 27 साल निवासी 13 न्यू गांधी पैलेस, इन्दौर हाल मुकाम फ्लेट नं. 201, सी ब्लॉक, गायत्री कुंज कालोनी इन्दौर।
- शुभम उर्फ शुब्बु पिता मदनलाल परमार उम्र 28 साल निवासी म.नं. 923/बी, राजनगर इन्दौर।
हाल मुकाम फ्लेट नं. 201, सी ब्लॉक, गायत्री कुंज कालोनी इन्दौर।

सराहनीय कार्य: उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, जिन राकेश चौहान, गौरव नगावत, नरेंद्र अम्करे, राधेश्याम वर्मा, मप्रआर निर्मला पाल, आर अजय जाट, लक्ष्मीकांत शर्मा, नरेंद्र सिरसाम, यशपाल रायपुरीया, अर्पित जायसवाल, अजय साल्वे एवं साइबर सेल से प्रआर शिवप्रताप सिंह सेंगर, सचिन चौहान व गीतिका कानूंगो सराहनीय भूमिका रही।

राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव में छार धार जिले के फूल



धार। उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशाअनुसार राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव-2026 का आयोजन गुलाब उद्यान परिसर, भोपाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया। पुष्प महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों द्वारा विविध प्रकार के फूलों की आकर्षक प्रदर्शनियाँ लगाई गईं। इस अवसर पर धार जिले के कृषकों द्वारा पॉलीहाउस तकनीक से उगाई गई विभिन्न प्रजातियों के फूलों की भव्य प्रदर्शनी प्रस्तुत

की गई। प्रदर्शनी में डच रोज, डिवाइन रोज, जरबेरा, लिसियथस, जिप्सोफैला, ब्लू एवं रेड डेजी, सनपलावर, लिमोनियम, क्रिसेंथेमम, एस्टर सहित अन्य फूल शामिल रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर उद्यानिकी विभाग एवं कृषकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों एवं प्रयासों की सराहना की गई। इस आयोजन में धार जिले के कृषकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पुष्प प्रदर्शनों को उत्कृष्टता के आधार पर कुल 12 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिससे जिले का नाम राज्य स्तर पर गौरवान्वित हुआ।

धार में पिंग लाइसेंस कैंप आयोजित 2 छात्र, 63 छात्राओं के लाइसेंस बने

परिवहन और महिला एवं बाल विकास विभाग का साझा आयोजन



धार। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं के लिए लॉगिंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए।

शिविर के दौरान अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की कर्मचारी खुशी पाया, सहायक वर्ग-3 एवं प्रदीप सोलंकी, सहायक वर्ग-3 द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत

छात्राओं एवं छात्रों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रतिनिधि चेतना राठौर द्वारा महिलाओं को सड़क सुरक्षा, सुरक्षित आवागमन एवं स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने हेलमेट एवं सीट बेल्ट की अनिवार्यता, गति सीमा का पालन, नशे की अवस्था में वाहन न चलाने, मोबाइल फोन के प्रयोग से बचने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के संबंध में विस्तार से समझाया। पिंग लाइसेंस कैंप में छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं के लिए लॉगिंग लाइसेंस बनाए गए, जिसमें 2 छात्र एवं 63 छात्रा सहित कुल 63 छात्र-छात्राओं के लॉगिंग लाइसेंस बनाए गए। शिविर में मौके पर ही दस्तावेज सत्यापन कर आवेदन की सुविधा दी गई, जिससे बड़ी संख्या में छात्राओं ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के कैंप को आत्मनिर्भर बनाना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें वैधानिक रूप से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करना है। महाविद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना की।

आम बजट 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी रविवार को कहा कि सरकार ने कोरी बयानबाजी के बजाय सुधारों का रास्ता चुना है। उन्होंने लोकसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि देश 'विकसित भारत' बनने की दिशा में कदम उठाता रहेगा। वित्त मंत्री ने 2026-2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश की। यह आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट है। यह उभरता भारत का बजट बताया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर बनाएं। नागरिक सामर्थ्य बढ़ाने पर जोर दिया। पर्यटन को प्रोत्साहन से युवाओं को अवसर।

उभरते भारत के सपने को संजोता बजट



- रक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान, कैंसर से जुड़ी दवाइयां सस्ती, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- हर जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा
- पीएम मोदी बोले- यह बजट विकसित भारत की उड़ान

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में

भंडारण (सीसीयूएस) दिसंबर 2025 में जारी किए गए रोडमैप के अनुरूप, में अगले पांच वर्षों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) तकनीकों के विकास,

इस बजट में किसानों को मिले अनगिनत तोहफे

- * महंगी फसलों पर फोकस
- * पहाड़ी इलाकों में खेती को बढ़ावा
- * चंदन की खेती पर भी दिया जोर
- * भारत विस्तार की शुरुआत
- * पशुपालन में रोजगार को बढ़ावा
- * एकपीओएस को प्रोत्साहन मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट 15 प्रतिशत बढ़ा, 17 कैंसर मेडिसिन ड्रग्स, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।



15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिपोर्ट नौवां बजट पेश करने से पहले रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने कहा यह बजट विकसित भारत की उड़ान है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, कार्बन कैप्चर, उपयोग और

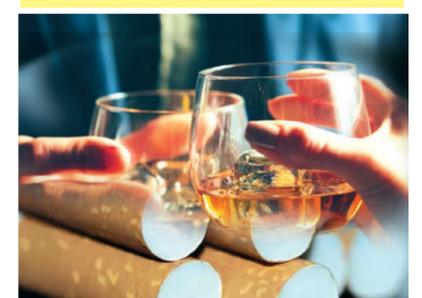
विस्तार और अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च स्तर की तैयारी हासिल करने के लिए 20,000 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखती हूँ। यह पहल पांच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन उद्योग में लागू की जाएगी।

क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?



- सोलर उपकरण, जूते, मोबाइल बैटरी होंगे सस्ते।
- कैंसर 17 दवाएं सहित 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती।
- थुगर की दवाई सस्ती होगी
- विदेश यात्रा पहले से सस्ती होगी।
- सीएनजी और बायोगैस भी सस्ती
- स्मार्टफोन और टैबलेट होंगे सस्ते
- बीडी सस्ती हुई
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए इंपोर्ट की गई दवाएं और औषधियां
- माइक्रोवेव ओवन के लिए जरूरी कंपोनेंट
- विमानों के इंजन सहित पाट या कंपोनेंट
- सोलर ग्लास सामग्री
- न्युक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट किए गए सामान
- क्रिकेट मिनरल के लिए पूंजीगत सामान

ये प्रोडक्ट हो जाएंगे महंगे



- कम कीमत वाले इंपोर्ट किए गए छाले
- पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
- एटीएम या कैश डिस्पेंसर मशीन और उसके पाट व कंपोनेंट
- विदेशी तरु के लिए फिल्म और ब्रॉडकास्टिंग उपकरण
- विडियाघर के लिए इंपोर्ट किए गए जानवर और पक्षी
- अमोनियम फॉस्फेट या नाइट्रो-फॉस्फेट उर्वरक और नेपथा उर्वरक
- कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग या वेंडिंग मशीनें
- अरंडी का ऑयल केक
- शराब
- स्केप
- खनिज सिगरेट

बजट में द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों एवं बौद्ध सर्किट पर जोर देने से असम को लाभ मिलेगा



सरकार के बजट में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के अवसर रचना विकास पर दिए गए जोर और बौद्ध सर्किटों की घोषणा से असम को लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर ध्यान केंद्रित करना राज्य के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्यम मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी शहरों और यहां तक कि मंदिर-नगरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्हें आधुनिक अवसर रचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास, पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के लिए 4,000 ई-बस के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

बजट की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं

- * इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- * कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5 प्रतिशत शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्रग्स की।
- * 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
- * आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
- * 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।
- * 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लेब्स बनाई जाएंगी।
- * करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।
- * इनकम टैक्स-स्लैब में बदलाव नहीं, रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा
- * स्वास्थ्य-कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्रग्स हटेंगी, इलाज सस्ता होगा
- * आयुर्वेद-भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी।



बजट 2026 वो फैसले जो बचाएंगे आपका पैसा

● बजट में मिडिल क्लास परिवार को मिली बचत की सुरक्षा- मिडिल क्लास के लिए बजट में सबसे बड़ा फोकस टैक्स और कस्टम्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर रहा। अब विदेश से यात्रा के दौरान एक लेपटॉप को पर्सनल सामान के साथ लाने पर स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टम डिक्लेरेशन और ड्यूटी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर लगने

वाला समय और तनाव दोनों कम होंगे। विदेश से स्थायी रूप से लौटने वालों के लिए घरेलू सामान लाने की ड्यूटी-फी सीमा बढ़ाई गई है। इससे अलावा सभी पर्सनल इंपोर्ट्स और गिफ्ट्स पर एक समान कस्टम ड्यूटी लागू की जा रही है, जिससे भ्रम खत्म होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म की गई है। वहीं 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े दवाइयों और विशेष भोजन को



- भी ड्यूटी-फी किया गया है।
- बजट में स्ट्रेंडेंट को विदेश में पढ़ाई के लिए मिला आसान मौका- विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों और

राशि पर टीसीएस घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 5 प्रतिशत होता था। इससे छात्रों पर शुरूआती वित्तीय बोझ कम होगा, एजुकेशन लोन पर निर्भरता घटेगी और इंपोर्टेड स्टडी मटेरियल या पार्सल की विलयर्स भी तेज होगी।

15 प्रतिशत/15एच एक ही विंडो से जमा किया जा सकेगा। छोट करदाताओं के लिए लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी। अब अफसरों के चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा, रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है जो भी नाममात्र शुल्क के साथ होगी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर ड्यूटी छूट बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

बजट पर किसने क्या कहा

आशा और आकांक्षाओं का बजट है: सीएम योगी

सीएम योगी ने केंद्रीय बजट 2026 कहा- आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक ये बजट है। इसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देना, महिलाओं के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण की व्यवस्था, नौजवानों के लिए हर क्षेत्र में अवसर। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बजट मददगार साबित होगा।

विकसित भारत बजट: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा, मैनुफैक्चरिंग से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, विकसित भारत बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण और अगले 25 सालों के रोडमैप को दर्शाने वाले इस बजट के लिए पीएम मोदी जी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी का हर भारतवासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन।

यह एक हम्पटी-डम्पटी बजट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह एक 'हम्पटी-डम्पटी बजट' है, सिर्फ शब्दों का खेल है, यह महिला-विरोधी, किसान-विरोधी और शिक्षा-विरोधी है। केंद्र देश की आर्थिक संरचना को नष्ट करना चाहता है।

पीतल के गहने पहनने पड़ेंगे

केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, अगर यही स्थिति बनी रही तो हमें सोने पर पीतल के गहने पहनने पड़ेंगे। केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह ऐसा बजट नहीं है जो किसी को राहत प्रदान करे।

बजट पर राहुल गांधी बोले संसद में बोलूंगा

केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, लोकसभा में विपक्ष के सदस्य राहुल गांधी ने कहा, मैं कल संसद द्वारा दिए गए मंच का उपयोग करते हुए बोलूंगा।

रामदास अठावले

केंद्रीय बजट 2026-27 पर आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने कहा, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। यह सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों प्रदान करेगा।

शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, हमें बहुत कम जानकारी मिली। 3-4 मुख्य बिंदु थे, लेकिन हम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का इंतजार कर रहे थे। यह कहां है? हम इसे केरल में चाहते थे। आयुर्वेद की हमारी एक लंबी परंपरा रही है।

सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भर के लिए

केंद्रीय बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह बजट जनता की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। इसमें अलावा, यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के विजन को मजबूत आधार प्रदान करता है। वहीं, इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं... ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद, इस बजट ने देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के हमारे संकल्प को बल दिया है।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डेली कॉलेज इंदौर में कार्यक्रम को किया संबोधित

सनातन व्यवस्था के संस्कार जीवन को संतुलित, स्वस्थ और मूल्यवान बनाने की है वैज्ञानिक पद्धति: मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में परंपरा और विज्ञान कभी अलग-अलग नहीं रहे। सनातन व्यवस्था के संस्कार केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ और मूल्यवान बनाने की वैज्ञानिक पद्धति है। गर्भ में पल रहे शिशु को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संस्कारित करना ही गर्भ संस्कार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में बनने वाले शासकीय चिकित्सालयों के भवनों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाए जाएंगे। प्रदेश के चिकित्सा विद्यालयों और उनसे जुड़े महाविद्यालयों में गर्भ संस्कार के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की जाएगी, शीघ्र ही इससे संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इंदौर के डेली कॉलेज में गर्भ संस्कार पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अंग वस्त्रम तथा श्रीफल भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुस्तक 'गर्भ संस्कार' का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक डॉ. अनिल गर्ग और डॉ. सीमा गर्ग हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपस्थित जन समुदाय को गर्भ संस्कार का प्रचार-प्रसार करने के लिए सकारात्मक प्रयास करने का संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास का सम्मान भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मातृत्व केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, गर्भ शरीर निर्माण के साथ संस्कार की पहली पाठशाला भी है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि 5-6 महीने से ही बच्चे पर माँ की भावनाओं और बाह्य

वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाभारत में अभिमन्यु तथा अन्य पौराणिक संदर्भ देते हुए कहा कि हमारे पूर्वज मानसिक और भावनात्मक विकास की गहरी समझ रखते थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आयुर्वेद की सामर्थ्य सर्वोपलब्ध है। कोविड काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोविड से बचाव के लिए सभी चिकित्सा पद्धतियों ने आयुर्वेद की प्रक्रियाओं अपनाया। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के महत्व को स्वीकारा गया है। वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी गर्भ संस्कार के महत्व को स्वीकार कर रहा है।

अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य श्री भय्याजी जोशी ने कहा कि भारत का चिंतन विश्व को संचालित करने का नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने का है। भारत 'सुपर राइट' बनेगा, जो जीवन के विविध क्षेत्रों में दुनिया को सही दिशा दिखाएगा। उन्होंने कहा कि सृष्टि के चक्र में भारत ने उत्थान और पतन दोनों देखे हैं, लेकिन उसकी

आत्मिक शक्ति और बीज रूप में सामर्थ्य इतनी मजबूत है कि वह फिर उठ खड़ा होने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण केवल शिक्षा या भौतिक संपदा से नहीं, बल्कि सुशिक्षा और सुसंस्कार से ही संभव है। मानव संपदा के बिना राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं। श्री जोशी ने कहा कि पश्चिमी दृष्टि मनुष्य को मशीन मानती है, जबकि भारतीय चिंतन मनुष्य को पूर्ण विकसित मनुष्य बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जब शस्त्र अयोग्य हाथों में चले जाते हैं तो दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए शक्ति के साथ संस्कार अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर पुण्य सलिला देवी अहिल्याबाई की श्रेष्ठ परंपरा वाली नगरी है। इंदौर से इस आयोजन का होना प्रतीकात्मक है, क्योंकि विचारों का प्रसूत प्रान्त मध्य से होता है। श्री जोशी ने युवाओं और दंपतियों से आग्रह किया कि शास्त्रों में निहित मूल्यों को केवल प्रस्तुति तक सीमित न रखें, बल्कि आचरण में उतारें। इसके लिए जनजागरण और व्यापक

आंदोलन आवश्यक है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति सही मार्ग पर चल सके और राष्ट्रनिर्माण में सहभागी बने। उन्होंने कार्यक्रम के शोधकर्ताओं, प्रयोगकर्ताओं और आयोजकों से कहा कि इस पहल की सार्थकता तभी है जब समाज इसे गंभीरता से अपनाए और अनुभवों को साझा कर आगे बढ़े।

कार्यक्रम को डॉ. अनिल कुमार गर्ग और डॉ. हिताश भाई जानी ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्पमित्र भागवत, विधायक श्री महेंद्र हाडिया और श्री गोलू शुक्ला, जनप्रतिनिधि, आरोग्य भारती के श्री अशोक वाणेश, श्री योगेंद्र महंत, श्री गणेश कोठारी, श्री विनोद अग्रवाल, श्री विक्रम सिंह पवार, डॉ. हिताश भाई जानी, श्री राधेश्याम शर्मा गुरु जी और डॉ. अनिल कुमार गर्ग सहित आध्यात्मिक-धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राज्यपाल ने नवीनीकृत लोकभवन मंदिर का लोकार्पण किया

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भक्तिभाव और विधि-विधान के साथ नवीनीकृत लोकभवन मंदिर का शुभ लोकार्पण किया। यह पावन समारोह रविवार को श्रद्धा, मनोचर्चा और पूजा-अर्चना के बीच संपन्न हुआ। श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक गरिमा के साथ हुए समारोह में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री पटेल का मंदिर परिसर आगमन पर पारंपरिक सनातन रीति से स्वागत किया गया। उन्होंने कलश के साथ मंदिर में मंगल प्रवेश कर विधि-विधान से कलश एवं ध्वज का पूजन किया। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की। वैदिक मंत्रोच्चारण और भक्तिमय वातावरण के मध्य माँ सरस्वती की पावन प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा और भक्तिभाव से दीप प्रज्वलित किया और प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्यपाल ने मंदिर में हुए नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्यों का अवलोकन किया। इसे आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में

महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

राज्यपाल श्री पटेल को बताया गया कि समग्र विकास कार्य मंदिर परिसर को अधिक सुशुद्ध, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य के साथ किया गया है। नवीनीकरण की संपूर्ण परियोजना 84 लाख 13 हजार 100 रुपये की लागत से संपन्न हुई है। इस कार्य में करीब 76 लाख 96 हजार रुपये के सिविल निर्माण तथा लगभग 7 लाख 16 हजार रुपये के विद्युत संबंधी कार्य कराए गए हैं। मंदिर परिसर में लगभग 2,700 वर्गफुट क्षेत्रफल का विशाल हॉल, श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 1,120 वर्गफुट क्षेत्र में भोजनशाला एवं भंडारा कक्ष और 560 वर्गफुट क्षेत्र में सुसज्जित रसोईघर भी तैयार किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भागवत, मुख्य अभियंता लोक निर्माण श्री संजय मस्के, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण श्री हरी शंकर जयसवाल, निर्यंत्रक हाउसहोल्ड लोकभवन श्रीमती शिल्पी दिवाकर, लोक निर्माण विभाग की सिविल, इलेक्ट्रिकल शाखा और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि सहित लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

26.5 टन गोमांस मिलने के मामले में प्रदर्शन

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 26.5 टन गोमांस मिलने के प्रकरण को लेकर विरोध और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को शीतलदास की बगिया में आयोजित धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन और तेज हो गया। कार्यक्रम स्थल पर करीब 30 से अधिक युवकों ने सामूहिक मुंडन कराया। आयोजकों ने इसे गोमाता की आत्मा की शांति और न्याय की मांग का प्रतीक बताया।

कार्यक्रम के दौरान दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने केवल सीमित कार्रवाई की है, जबकि प्रकरण में सलिल बताए जा रहे सरकारी और नगर निगम कर्मियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की मांग-जय माँ भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू ने कहा कि संगठन इस मामले में असलम और शोएब के साथ-साथ उन सभी सरकारी कर्मचारियों और नगर निगम कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिनकी भूमिका सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला सिर्फ अवैध गोमांस का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और संरक्षण का भी है।

भानु हिंदू ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि मामले में शीर्ष स्तर पर ध्यान आकर्षित हो सके।

आरएसएस के सह-क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख बने हितानंद शर्मा

4 साल पहले बनाए गए थे भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री ; 3 प्रचारकों की भी जिम्मेदारी बदली

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की आरएसएस में वापसी हो गई है। अब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मध्य क्षेत्र सह-बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब जबलपुर उनका केन्द्र यानी मुख्यालय होगा, जहां से वे एमपी और छत्तीसगढ़ में संघ की नई जिम्मेदारी संभालेंगे।



केडर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है।

तहसील प्रचारक से प्रदेश महामंत्री तक पहुंचे

हितानंद के साथ आरएसएस के तीन अन्य प्रचारकों की भूमिका बदली गई है। सुरेंद्र मिश्रा अब पूर्व सैनिक सेवा परिषद में काम करेंगे। मुकेश त्यागी ग्राहक पंचायत में काम संभालेंगे। वहीं ब्रजकिशोर भागवत क्षेत्र गो सेवा प्रमुख बनाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, संगठनात्मक रणनीति के तहत यह बदलाव किया गया है। हितानंद शर्मा मूल रूप से अशोकनगर (चंबल क्षेत्र) के निवासी हैं। वे लंबे समय से विद्या भारती संगठन से जुड़े रहे हैं। संघ पृष्ठभूमि के चलते संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हितानंद शर्मा की नई जिम्मेदारी तय होने के बाद नया प्रदेश संगठन महामंत्री को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि, पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

आरएसएस से गहरा जुड़ाव, संगठन में रही अहम भूमिका

मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री बनने से पहले वे सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्ष 2020 में उन्हें प्रदेश सह-संगठन महामंत्री बनाया था, जबकि 2022 में वे सुहस्र भगत के स्थान पर प्रदेश संगठन महामंत्री बने थे।

आरएसएस में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है, खासकर ग्वालियर-चंबल अंचल में। संगठन के भीतर उन्हें अनुशासन और

10 साल विद्या भारती का काम देखा

हितानंद शर्मा तत्कालीन संगठन महामंत्री सुहस्र भगत के सह संगठन महामंत्री के रूप में भाजपा में आए थे। पार्टी से पहले उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक विद्या भारती का काम देखा। उससे भी पहले वे तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक और विभाग प्रचारक जैसे दायित्व निभा चुके हैं।

यूजीसी के विरोध में बुलाया शिवपुरी बंद, बीजेपी के बजट कार्यक्रम में काटा बवाल, तोड़ीं कुर्सियां

शिवपुरी (नप्र)। रविवार को यूजीसी कानून को लेकर बुलाए गए भारत बंद को लेकर कई जगह पर विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। शिवपुरी और नरवर में भाजपा के बजट लाइव प्रसारण कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। करैरा में यूजीसी कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा मचाते हुए कुर्सियां तोड़ दी और नारेबाजी की। इस दौरान यहां पर अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इसके साथ ही नरवर में विरोध के दौरान एक दुकानदार के साथ मारपीट कर दी, जिससे यहां पर माहौल गरमाया गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

शिवपुरी-करैरा में हंगामा

रविवार को शिवपुरी सहित जिले के अंचल में यूजीसी कानून के विरोध में भारत बंद बुलाया गया। यह बंद उस समय उठा हो गया, जब बीजेपी का लाइव बजट कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान यूजीसी कानून का विरोध करते हुए लोग पहुंच गए और हंगामा काट दिया। साथ ही कार्यक्रम में रखी कुर्सियां तोड़ दीं।



बीजेपी के विरोध में नारे लगाए जाने लगे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति संभाली है। इससे बजट कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। वहीं, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत को जाना पड़ा।

मारपीट और दुकानों में की तोड़फोड़

भारत बंद के दौरान करैरा में बाजार बंद कराते समय तिल रोड स्थित एक ऑनलाइन दुकान और कच्ची गली में एक गारमेट दुकान में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। वहीं, नरवर कस्बे की मौजूद मारकेट में व्यापारी ने दुकान नहीं बंद की तो प्रदर्शनकारियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। बाद में पुलिस ने यहां पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठी चलाई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूजीसी के नए कानून पर रोक लगा दिया है। वहीं, मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सर्वगों का प्रदर्शन जारी है। विरोध के तहत ही सर्वगों ने शिवपुरी में बंद बुलाया था। बंद के दौरान बड़ी संख्या में यूजीसी के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भाग रहे तेंदुए! बाघों के डर से बनाई 'नई टेरिटरी'

दमोह (नप्र)। बुंदेलखंड के जंगलों से एक सुखद और रोमांचक खबर सामने आ रही है। दमोह जिले का तेंदुखेड़ा के जंगल, तेंदुओं के स्थायी टिकाने के रूप में नई पहचान बन रहा है। कभी इक्का-दुक्का दिखने वाले तेंदुए अब यहां आए दिन नजर आने लगे हैं। इन्होंने अपनी अलग टेरिटरी बना ली है। वन विभाग के अनुमान के मुताबिक, टाइगर रिजर्व और दमोह के आसपास के जंगलों को मिलाकर तेंदुओं का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है।



यह कौतूहल का विषय है। हाल ही में तारादेही मार्ग पर बहेरिया के पास एक तेंदुए को पेड़ पर आराम करते देखा गया, वहीं दमोह मार्ग पर कसा चौकी के पास भी राहगीरों का सामना इस शिकारी से हुआ।

बाघों की बढ़ती तादाद ने बदला तेंदुओं का पता!-

और किशन को बसाया गया था। धीरे-धीरे कर इनकी संख्या में इजाफा हुआ और वर्तमान में यहां छोटे-बड़े बाघ मिलाकर 28 से अधिक बाघ बताए जा रहे हैं। बाघ अपनी टेरिटरी बड़ा रहे हैं, इस कारण तेंदुए अपना पुराना टिकाना छोड़कर अभयारण्य के आसपास के बाहरी व सुरक्षित जंगली इलाकों में नई टेरिटरी बसा रहे हैं।

तेंदुआ, टाइगर से बहुत डरता है, सामना नहीं करता-तेंदुआ, बाघ से बहुत डरता है। जहां बाघ की मौजूदगी होती है, वहां से तेंदुआ अपनी जगह बदल लेता है। यह टाइगर का सामना नहीं करता। टाइगर दिख जाए तो यह सीधे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर रहता है। यही कारण है कि टाइगर रिजर्व से निकलकर अब तेंदुए तेंदुखेड़ा उप वनमंडल की रेंजों में अपना नया बसेरा बना रहे हैं।

तेंदुओं के बारे में दिलचस्प बातें

ये कैट फैमिली के सबसे चालाक सदस्य हैं, जो 50 किमी तक शिकार की तलाश में दौड़ सकते हैं। ये खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये गुफाओं और ऊंचे पेड़ों को डालियों पर रहते हैं। ये अक्सर इसीनी बस्तियों के पास रहते हैं, लेकिन इसानों को देखते ही छिप जाते हैं। इनका मुख्य भूखंड रात में होता है, ताकि बाघ और लकड़बग्घों से टकराव न हो। ये छोटे हिरण, खरागोश से लेकर छोटे जानवरों और पक्षियों तक का शिकार करते हैं। कुत्ता इनका प्रिय भोजन माना जाता है।

जैव विविधता के लिए 'गुड न्यूज'

वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने के बाद जंगलों की कटाई और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगी है। उप वनमंडल अधिकारी प्रतीक दुबे ने स्थानीय मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तेंदुओं की बढ़ती संख्या एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। वन विभाग की सक्रिय निगरानी और सुरक्षा उपायों के चलते अब वे वन्यजीव निडर होकर विचरण कर रहे हैं।

राजस्व मामले हल नहीं करने पर कार्रवाई

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फार्म रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व योजना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की अधिकारीवार प्रगति की गहन समीक्षा की। भू-राजस्व वसूली की विशेष रूप से समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए की भू-राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप भू-राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। इसी तरह उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की अवैध कॉलोनी निर्माण और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा तथा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रोशन राय, रिंकेश वैश्य तथा निशा डामोर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।



नाबालिग की हत्या, घर के पास ही उसका शव मिला, एक पकड़ाया

30 मीटर दूर स्थित एक बिल्डिंग में पलंग के अंदर शव मिला

इंदौर। शहर के श्रीनगर कांकड़ इलाके में 13 वर्षीय नाबालिग अली कादरी की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अली की गला चोटकर हत्या कर दी गई और उसका शव घर से महज 30 मीटर दूर स्थित एक बिल्डिंग में पलंग के अंदर छिपाकर रखा गया।

घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल है। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, अली शुक्रवार शाम करीब 7.30 बजे तक चिंम के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात को वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, जब कोई सुराग नहीं मिला तो एमआईजी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू की गई। एमआईजी थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि

सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर अली को दो युवकों के साथ जाते हुए देखा गया।

इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और अली की आखिरी लोकेशन के आधार पर घर के पास ही स्थित एक बिल्डिंग तक पहुंची। वहां तलाशी के दौरान पलंग के अंदर अली का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रहान ने अपने साथी के साथ मिलकर अली की गला चोटकर हत्या की और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को पलंग में छुपा दिया। पुलिस ने बिल्डिंग की छत से अली का बैग, किताबें और जैकेट भी बरामद की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हत्या के पीछे की वजह क्या रही, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।